घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर, वर्ष 23, अंक - 04- बुधवार 04- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 , मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

रिलायंस के अनिल अंबानी समूह की 510 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां कुर्क



नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस में अनिल अंबानी समूह के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में 510 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें विमान, बैंक खातों में जमा राशि,सावधि जमा, अचल संपत्तियां,निवेश और बकाया भुगतान शामिल हैं। इस कार्रवाई के साथ समूह के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच किए जा रहे विभिन्न मामलों में अब तक करीब 23,100 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क या जब्त की जा चुकी हैं। ईडी के अनुसार,यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के बैंक धोखाधड़ी मामले में 247.12 करोड़ रुपये और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड तथा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों से संबंधित है। आरकॉम मामले में दो चार्टर्ड विमान,छह भूखंड और महाराष्ट्र स्थित एक कार्यालय परिसर कुर्क किया गया है। वहीं,रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामलों में तमिलनाडु की दो पवन चक्कियां, बैंक खातों में जमा राशि,सावधि जमा और निवेश तथा बकाया भुगतान से जुड़ी संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी ने दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई),दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा और मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी।

भारत ने कभी जीएम उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं दी,डेयरी क्षेत्र भी नहीं खोलेगा : पीयूष गोयल



नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि भारत ने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में अपने डेयरी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों या अन्य देशों के लिए नहीं खोला है और न ही भविष्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों के आयात की अनुमति देगा। गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने किसी भी संवेदनशील वस्तु पर ''कभी भी''समझौता नहीं किया है और व्यापार समझौतों में हमेशा अपने किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म,लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के हितों की रक्षा की है।''उन्होंने व्यापार समझौतों से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा,''हम कुछ कृषि उत्पादों और कुछ ऐसी वस्तुओं के मामले में बाजार खोलने को लेकर बहुत संवेदनशील हैं जिनमें हमारी मजबूत स्थिति है, जैसे समुद्री उत्पाद। हम अपना डेयरी क्षेत्र खोलने को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। वास्तव में,आज तक हमने किसी के लिए भी डेयरी क्षेत्र नहीं खोला है। वाणिज्य मंत्री ने कहा,''हम भारत में किसी भी जीएम उत्पाद को आने देने के मामले में बहुत संवेदनशील हैं। हमने कभी इसकी अनुमति नहीं दी है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी धार्मिक संवेदनशीलताओं को लेकर भी सतर्क हैं।'' उन्होंने कहा कि ''अक्सर विदेशों में डेयरी उत्पाद बनाने के दौरान बछड़े के मांस या 'रेनेट' का इस्तेमाल किया जाता है...हम भारत में इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

श्रीनगर से सांसद मेहंदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी,जनसभा में सांसद पद से इस्तीफे का ऐलान



श्रीनगर,03 नवंबर 2026। नेशनल कॉन्फ्रेंस से श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संसद की सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान किया। मंगलवार को बडगाम में जनसभा करके उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। रूहुल्लाह ने कहा- यह आजादी का फैसला है। मैं एक शहीद की विरासत और पाक खून की नस्ल का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपनी आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आज दोपहर 2:40 बजे से मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हूं। उन्होंने बडगाम में पिता आगा सैयद मेहंदी की 26वीं पुण्यतिथि पर जनसभा बुलाई थी। रूहुल्लाह ने बताया कि वे अपना इस्तीफा मुहम्मद अशरफ मट्टू के जरिए पार्टी को भेजेंगे। उन्होंने पार्टी पर लोगों की गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाया। साथ ही उमर अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बीजेपी के दबाव में रुख बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को अपने बेटे को कुरान पढ़ाना चाहिए। रुहुल्लाह बडगाम से तीन बार विधायक रह चुके हैं और 2024 में श्रीनगर से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 25 विधायकों ने रविवार को पार्टी ही नेतृत्व को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया थी। विधायकों ने मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 21 हजार करोड़ की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन किया

पहले गरीबी खत्म करने के वादे होते थे,अब जमीनी स्तर पर काम हो रहा : पीएम मोदी



नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई पीढ़ियों ने गरीबी खत्म करने के वादे सुने हैं। पहले गरीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित थी,लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए जमीन पर काम हो रहा है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने पुणे मेट्रो की करीब 21,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। आज दुनिया में भारत की चर्चा दो और वजहों से हो रही है। पहली, दुनिया में मुश्किल हालात के बावजूद भारत सबसे तेज आर्थिक विकास करने वाला देश बना हुआ है। दूसरी, सिर्फ 10 से 12 साल में भारत के 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र में खराब मौसम से कई किसान परेशान हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में जल संरक्षण के लिए काम हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से किसानों को नुकसान हुआ है। इस मुश्किल समय में एन सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। देश के सैकड़ों छोटे शहरों को भी विकास के केंद्र के रूप में तैयार करना होगा। इसी सोच के साथ इस साल फरवरी में अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार इस फंड के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे रही है। पुणे मेट्रो लाइन का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हुआ है। यह विकास का ऐसा मॉडल है, जिसकी सफलता से देश की तरक्की को और रफ्तार मिलेगी। पुणे मेट्रो के विस्तार से लोगों का समय बच रहा है और सफर आसान हो रहा है। जब किसी शहर में लोगों का समय बचता है, तो वहां काम करने की क्षमता बढ़ती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। अर्थव्यवस्था बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग, दोनों को लाभ मिलता है।

पुणे मेट्रो की लाइन-3 करीब 23 किलोमीटर लंबी है...

पुणे मेट्रो की लाइन-3 यानी पिंक लाइन करीब 23 किलोमीटर लंबी है। यह मान से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाती है। इससे हिंजवड़ी आईटी हब और शिवाजीनगर के बीच मेट्रो सेवा शुरू होगी। इससे हजारों आईटी कर्मचारियों और दूसरे यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी। पीएम ने पुणे मेट्रो के दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। इस पर करीब 13,500 करोड़ खर्च होंगे। इसमें मेट्रो की लाइन 2ए,2बी, 4 और 4ए बनाई जाएंगी।

एक जगह अनिश्चितकाल तक धरना नहीं दे सकते

प्रदर्शन एक का नहीं,सबका अधिकार : सुप्रीम कोर्ट



नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोई भी संगठन प्रदर्शन के लिए किसी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों पर भी एक तय समय-सीमा होनी चाहिए,ताकि दूसरे संगठनों को भी अपनी बात रखने का मौका मिल सके। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा...आप हमेशा के लिए किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। वहां किसान,पत्रकार,मजदूर और दूसरे प्रदर्शनकारी कहां जाएंगे? सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी.मोहना की बेंच दिल्ली में अक्टूबर में हुए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, लोगों की हिरासत, निगरानी (सर्विलांस),प्रदर्शन स्थलों और कारोबारियों को हुए नुकसान से जुड़े मामले शामिल हैं।

व्यापारियों ने कहा...त्योहारों में 2000 करोड़ का नुकसान

सुनवाई के दौरान दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। त्योहारों के सीजन में दुकानें बंद रहीं और बिक्री घट गई। उन्होंने दावा किया कि कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अगर त्योहारों के सीजन में बिक्री नहीं होगी तो व्यापारियों और उनसे जुड़े लोगों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कोर्ट से अगले दो महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन या धरने पर रोक लगाने की मांग की।

कॉकरोच जनता पार्टी को एक दिन की अनुमति मिली, 17 दिन तक बैठे रहे...

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी,लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिन तक वहां बैठे रहे। मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर मार्च भी किया। संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है। बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो संगठन बंद या प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

भारत ने सोमालिया के तट के पास समुद्री लुटेरों से अपहृत जहाज 'अजिनी' छुड़ाया

नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के पास 48 घंटे से अधिक समय तक चले ऑपरेशन में कमांडो कार्रवाई करके सशस्त्र समुद्री लुटेरों के कब्जे से मछली पकड़ने वाले अपहृत जहाज 'अजिनी'को मुक्त कराया है। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 20 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया और ऑपरेशन के दौरान किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल, पिछले महीने की शुरुआत में सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास सशस्त्र समुद्री लुटेरों के एक समूह ने नौसेना को मछली पकड़ने वाले जहाज'अजिनी'का अपहरण कर लिया था। यह हाईजैकिंग बड़ा समुद्री सुरक्षा खतरा था, जिसमें इस बात की संभावना थी कि इस जहाज का इस्तेमाल इस इलाके में मर्चेंट शिपिंग पर और समुद्री डाकुओं के हमले करने के लिए 'मदर शिप'के तौर पर किया जा सकता है। इसकी सूचना मिलने पर भारतीय नौसेना ने मिशन पर तैनात एक युद्धपोत को कार्रवाई के लिए तत्काल रवाना किया। इसमें एक समुद्री निगरानी विमान का भी सहयोग लिया गया। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि आपसी तालमेल से लगातार



निगरानी के बाद जहाज का पता लगाया गया और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। नौसेना ने अपहृत जहाज की गतिविधि को सीमित करने और उसे भागने से रोकने के लिए सुनियोजित गैर-घातक उपाय अपनाया। भारतीय नौसेना ने त्वरित और सुव्यवस्थित सामरिक कमांडो कार्रवाई करते हुए जहाज को अपने नियंत्रण में लिया।

मोदी जी देश विरोधी कौन..बहस कीजिए जगह-जज आप चुनिए : राहुल गांधी

शाह बोले...किसी भी मुद्दे पर बहस को तैयार

नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी को बहस का चैलेंज दिया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर 1.50 मिनट के वीडियो में कहा, '24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए,डिबेट कीजिए मेरे साथ।' राहुल ने कहा...देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर,फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, स्कैम कैसे हुई, क्यों हुई,इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडाणी का केस बंद क्यों हुआ,एपस्टीन-ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर खुलकर डिस्कशन होगा। आ जाइए,डरिए मत। उधर,गृहमंत्री अमित शाह ने कहा,'मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद चलने दो। हम विशेष सत्र बुलाकर SIR पर चर्चा के लिए तैयार हैं।'राहुल ने कहा,'बाकी चीजों पे आपने डिफेमेशन केस लगा रखा है,शायद 45 डिफेमेशन केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पर,फॉरेन कनेक्शन पर आप डिफमेशन नहीं लगा रहे हो।

भारत ने पहली बार एक लॉन्चर से 2 मिसाइलें दागीं

500 किलोमीटर दूर 2 टारगेट तबाह,टेस्ट सफल,पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होगी

नई दिल्ली,03 नवंबर 2026। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी खासियत यह है कि एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें लगातार दागी जा सकती हैं। 500 किलोमीटर तक मार करने वाली यह मिसाइल दुश्मन के अलग-अलग ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसे क्वासी-बैलेस्टिक मिसाइल कहा जाता है,क्योंकि यह उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। इस परीक्षण के पहले 2किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया गया था। रूस और अमेरिका पहले से ही इस तरह की मल्टी-मिसाइल लॉन्च क्षमता वाले सिस्टम विकसित कर चुके हैं। हालांकि,भारत ने यह क्षमता अपनी स्वदेशी तकनीक से विकसित की है।

क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या है : आम बैलिस्टिक मिसाइल सीधे ऊपर जाकर फिर नीचे आती है,रास्ता पहले से पता चल जाता है।



प्रलय लो-ट्रेजेक्टरी पर जाती है,बीच में ही दिशा बदल सकती है,टर्मिनल फेज में मैन्युवर करती है। इसलिए दुश्मन का एयर डिफेंस इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। इसे आर्मी और एयरफोर्स दोनों में शामिल किया जाना है। पाकिस्तान के साथ एलओसी पर ऐसे शॉर्ट रेंज,हाई प्रिसीजन हथियार गेम-चेंजर माने जा रहे हैं।

सॉल्वो टेस्टिंग को समझें...

- **साल्वो का मतलब :** एक साथ कई फायर। नॉर्मल टेस्ट में एक लॉन्चर से एक मिसाइल जाती है,टारगेट हिट करती है। साल्वो टेस्टिंग में एक ही लॉन्चर से 30-60 सेकंड के अंतर में दो मिसाइलें दागी जाती हैं, दोनों का टारगेट अलग होता है।
- **मुश्किल क्यों है :** पहली मिसाइल के निकलते ही लॉन्चर हिलता है, धुआं, हीट और वाइब्रेशन पैदा होता है। उसी हिले हुए लॉन्चर से दूसरी मिसाइल को सटीक जाना होता है। अगर नेविगेशन सिस्टम में जरा भी एरर आया तो दूसरी मिसाइल फेल।
- **भारत के लिए फायदा :** युद्ध में दुश्मन के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का एक एयरबेस और उसका रडार-दोनों 500 चरूदूर से एक ही ट्रक से तबाह।

नई पीढ़ी अपनी जड़ों,भाषा और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़े : निर्मला सीतारमण

वाराणसी,03 नवंबर 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, भाषा और शास्त्रीय परंपराओं की ओर लौटना चाहिए। भारत की विविधता और एकता को बनाए रखने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों से भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों को समझने तथा देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजने का आह्वान किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री मंगलवार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के स्वतंत्रता भवन सभागार में कर्नाटक संगीत के महान संगीतकार मुत्तुस्वामी दीक्षितर की 250वीं जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने महान संगीतकार के सम्मान में 250 रुपये के स्मारक सिक्के का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी बीएचयू के भारतीय ज्ञान परंपरा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-आईकेएस) की ओर से किया गया। वित्त



मंत्री ने बीएचयू के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया।

दीक्षितर की रचनाओं में भारतीय तीर्थों और मंदिरों का जीवंत चित्रण : निर्मला सीतारमण ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर की संगीत रचनाओं की विशिष्टता, आध्यात्मिकता और विद्वत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी कृतियां केवल संगीत रचनाएं नहीं हैं,बल्कि भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत का विस्तृत परिचय भी कराती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न तीर्थस्थलों और मंदिरों की विशेषताओं को स्वर दिया। काशी का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दीक्षितर ने देवी की स्तुति में काशी विश्वलक्ष्मी का वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में मंदिरों के पवित्र वृक्षों (स्थलवृक्ष),आसपास की नदियों,पर्वतों और भौगोलिक विशेषताओं का भी उल्लेख मिलता है। इस लिहाज से उनकी कृतियां किसी स्थान की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विशेषताओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

दीक्षितर की रचनाओं को बताया 'लोनली प्लैनेट' जैसा : वित्त मंत्री ने मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं की तुलना प्रसिद्ध यात्रा-पुस्तक श्रृंखला 'लोनली प्लैनेट' से की। उन्होंने कहा कि आज किसी अनजान स्थान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लोग गूगल का सहारा लेते हैं, जबकि पहले यात्री'लोनली प्लैनेट' जैसी पुस्तकों के माध्यम से किसी स्थान के दर्शनीय स्थलों, खानपान और विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते थे। उन्होंने कहा कि दीक्षितर की रचनाएं भी इसी तरह भारत के विभिन्न स्थानों,मंदिरों और उनकी विशिष्टताओं से परिचित कराती हैं। महान चित्रकारों की तरह वे अपनी प्रत्येक रचना में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ते थे।

सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को नई धार देने की तैयारी में : रक्षामंत्री राजनाथ

जैसलमेर, 03 नवंबर 2026। दुनिया में बदलते युद्ध के तौर-तरीकों और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को नई धार देने की तैयारी में है। अब युद्ध के मैदान में केवल पारंपरिक हथियार ही नहीं,बल्कि ड्रोन,मिसाइल,आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां और सटीक हमला करने वाली तकनीक भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेनाओं के आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बताया। रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में देश का रक्षा बजट बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें सेनाओं के आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य आधुनिक सैन्य संसाधनों से लैस सेनाओं के साथ घरेलू रक्षा उद्योग को भी मजबूत बनाना है,ताकि भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला देश में विकसित तकनीक और उपकरणों से किया जा सके।

राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध



और इजराइल-ईरान संघर्ष जैसे घटनाक्रमों ने युद्ध की बदलती प्रकृति को सामने रखा है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन, मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों की भूमिका तेजी से बढ़ी है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सरकार वित्तीय संसाधनों, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता तथा मानव संसाधन और सैन्य संरचनाओं में सुधार पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य केवल नए हथियार खरीदना नहीं,बल्कि सैनिकों की क्षमता,युद्ध की तैयारी और तकनीकी दक्षता को एक साथ मजबूत करना है।

संपादकीय

मुनाफाखोरी की गिरफ्त में मरीज

भारत ने पिछले तीन दशकों में चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। दुनिया की हर पांच में से एक जेनेरिक दवा भारत में बनती है। इसलिए भारत को 'विश्व फार्मेसी' कहा जाता है। भारत ग्लोबल साउथ सहित कई देशों के लिए चिकित्सा पर्यटन का विश्वसनीय केंद्र भी है,लेकिन इस उपलब्धि के पीछे एक चिंताजनक तस्वीर भी है, जो हमारे मेडिकल स्टोर पर रोज दिखाई देती है। यह तस्वीर दवाओं की ऊंची कीमतों और उससे भी गंभीर नकली तथा घटिया दवाओं के बढ़ते कारोबार की है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं,बल्कि नैतिक संकट भी है,जहां मुनाफे की लालसा जीवन के मूल्य पर भारी पड़ रही है। ध्यान देने योग्य है कि दवाओं की कीमत और गुणवत्ता केवल उनके निर्माण की लागत और वैज्ञानिक प्रक्रिया से नहीं,बल्कि निर्माता से मरीज तक पहुंचने वाली आपूर्ति व्यवस्था से भी प्रभावित होती है।

इसी क्रम में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एनपीपीए) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने कैंसर की 137 गैर-अनुसूचित दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है। ये दवाएं अब तक मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं थीं। एनपीपीए की जांच में सामने आया कि इन दवाओं पर 700 प्रतिशत तक ट्रेड मार्जिन वसूला जा रहा था। उदाहरण के लिए, कंपनी जिस दवा को 10 हजार रुपये में स्टाकिस्ट को बेचती थी, उसका अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 50 हजार रुपये तय किया जाता था। यानी बिचौलियों,वितरकों,अस्पतालों की फार्मेसी और करों के नाम पर कीमत में 40 हजार रुपये का अंतर था। सरकार ने ट्रेड मार्जिन को एमआरपी के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इससे एमआरपी में 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है। इसी व्यवस्था के तहत एनपीपीए ने 2019 में 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित किया था। तब उनकी कीमतों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। मार्जिन सीमित करने का अर्थ कंपनियों की कमाई घटाना नहीं है। निर्माता को उसका निर्धारित मूल्य मिलता रहेगा,जबकि बिचौलियों का असामान्य मुनाफा घटेगा। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि मूल्य नियंत्रण से नवाचार प्रभावित होगा। यहां एक सवाल यह है कि क्या केवल ट्रेड मार्जिन सीमित करने से कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज सस्ता हो जाएगा? ट्रेड मार्जिन को नियंत्रित करना और निर्माता द्वारा तय की गई कीमत को नियंत्रित करना दो अलग-अलग पहलू हैं। यदि निर्माता शुरुआती कीमत ही बहुत अधिक तय करता है, तो 30 प्रतिशत मार्जिन की सीमा के बाद भी दवा महंगी रहेगी। इसके अलावा कंपनियां आर्टिफिशियल डिस्काउंट का तरीका भी अपनाती हैं। वे चुनिंदा बड़े कारपोरेट अस्पतालों को कुछ यूनिट पर भारी छूट देकर कम बाजार मूल्य का आभास देती हैं,जबकि बाकी दवाएं ऊंची कीमत पर ही बिकती हैं। इससे नियामक के लिए दवा का वास्तविक बाजार मूल्य तय करना कठिन हो जाता है। इसलिए ट्रेड मार्जिन नियंत्रण के साथ कीमतों की सख्त निगरानी और बिक्री तथा छूट की पारदर्शी रिपोर्टिंग भी जरूरी है। यह व्यवस्था सभी दवाओं पर लागू होनी चाहिए।

नकली और घटिया दवाओं की समस्या महंगी दवाओं से भी जुड़ी है। जब दवाएं बहुत महंगी हो जाती हैं तो नकली दवाओं के लिए बाजार तैयार हो जाता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार,बाजार में तीन से पांच प्रतिशत दवाएं मानक गुणवत्ता से कम या नकली हैं। सरकार को कानून और तकनीक के जरिये नियमन एवं निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। एनपीपीए को स्वास्थ्य संस्थानों और अन्य संबंधित पक्षों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए,जो चार पहलुओं पर नजर रखे-मरीज का कुल बिल,दवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की बिलिंग और इलाज तक पहुंच। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कीमतें घटने के बाद संबंधित दवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में उपलब्ध रहें,क्योंकि कंपनियां अक्सर कम मुनाफे वाली पुरानी दवाओं का उत्पादन बंद कर देती हैं। अब 300 से अधिक दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य है,जिसे स्कैन करके असली और नकली दवा की पहचान की जा सकती है। इसका दायरा धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन कर नकली दवा बनाने को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है,जिसमें आजीवन कारावास तक का प्रविधान है। पिछले दो वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का पालन नहीं करने वालीं 150 से अधिक कंपनियों के लाइसेंस रद किए गए हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का विस्तार हो। आज 14 हजार से अधिक केंद्रों पर दो हजार से अधिक दवाएं 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। डाक्टरों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे पर्चे पर किसी खास कंपनी की दवाएं अस्पष्ट लिखने के बजाय स्पष्ट रूप से जेनेरिक दवाओं के नाम लिखें। आज चिकित्सा तंत्र मुनाफाखोरी की गिरफ्त में है। इसका एक कारण चिकित्सा शिक्षा का महंगा और सीमित होना भी है।

आजम खान की गिरफ्तारी : कानून का तकाजा या सियासी टकराव का नया अध्याय?

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को गाजियाबाद की विशेष पी एम एल ए अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें डासना जेल में रखा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब उनसे पुलिस कस्टडी में पूछ-ताछ के लिए रिमांड लेने की तैयारी कर रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उसके वित्तीय प्रबंधन में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। आजम खान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश की राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका,राजनीतिक जवाबदेही और कानून के निष्पक्ष इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है। लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोपरि होता है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक कद कितना भी बड़ा क्यों न हो,यदि उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमित-ताओं या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं तो जांच होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों की जवाबदेही आम नागरिकों से कम नहीं,बल्कि अधिक होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही आवश्यक है कि जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप हो। किसी व्यक्ति को राजनीतिक पहचान के आधार पर न तो अपराधी माना जा सकता है और न ही राजनीतिक सहानुभूति के आधार पर आरोपों से मुक्त किया जा सकता है।



सौरभ वार्ष्णेय
उत्तमनगर,नई दिल्ली

आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक चर्चित और प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। रामपुर की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने वाले आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सांसद के रूप में उनकी राजनीतिक भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके विरुद्ध दर्ज विभिन्न मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों ने उनके राजनीतिक जीवन को लगातार प्रभावित किया है। अब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई ने उनके सामने एक नई कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आजम खान लगभग 11 महीने जेल में रहने के बाद शनिवार को रामपुर जेल से बाहर आए थे। लेकिन उनकी रिहाई की खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी और प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें दूसरे मामले में हिरासत में ले लिया। रविवार को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब ईडी उनसे जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना,उसके



निर्माण में इस्तेमाल धन,फंडिंग के स्रोत और कथित मनी ट्रेल के संबंध में पूछताछ करना चाहती है। यह पूरा घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल जौहर यूनिवर्सिटी के वित्तीय प्रबंधन का है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि किसी संस्थान को सरकारी सहायता, निजी दान या अन्य वित्तीय स्रोतों से धन मिला है तो उसका पूरा हिसाब-किताब सार्वजनिक और कानूनी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। आखिर धन कहां से आया,किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ और उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर सामने आना चाहिए। यदि सरकारी धन के दुरुपयोग या अवैध लेन-देन के प्रमाण मिलते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों के अनेक नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आते रहे हैं। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है,जबकि सरकार और जांच एजेंसियां इन कार्रवाइयों को कानून के तहत की गई जांच बताती हैं। ऐसे में जनता के मन में उठने वाले संदेहों को दूर करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसका सबसे प्रभावी तरीका यही है कि जांच एजेंसियां अपने प्रत्येक कदम को ठोस साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर उचित ठहराएं।

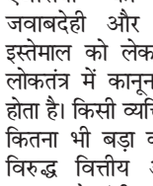
आजम खान के मामले में भी समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन इन आरोपों की सत्यता का फैसला अदालत और उपलब्ध साक्ष्य ही करेंगे। इसी तरह ईडी के आरोपों को भी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। जांच और मुकदमे के बीच अंतर समझना जरूरी है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का अर्थ दोष सिद्ध होना नहीं है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी बचाव का अधिकार देता है। आजम खान को भी यह अधिकार पूरी तरह मिलना चाहिए। इस प्रकरण का एक व्यापक पक्ष शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है। जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान केवल किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं होते,बल्कि उनसे हजारों विद्यार्थियों और कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा होता है। यदि वित्तीय अनियमितताओं के कारण किसी विश्वविद्यालय की गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो सबसे अधिक नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। इसलिए जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। राजनीतिक दलों को भी इस मामले में संयम बरतने की जरूरत है। सत्ता पक्ष को जांच को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने से बचना चाहिए और विपक्ष को भी हर कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में न तो जांच एजेंसियां किसी सरकार की निजी संस्था हैं और न ही राजनीतिक नेता कानून से ऊपर हैं। इसी तरह सरकार को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह जांच के नाम पर किसी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करे।

आजम खान का मामला केवल एक नेता की गिरफ्तारी या जेल भेजे जाने तक सीमित नहीं है। यह देश की न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही की कसौटी भी है। ईडी को यदि वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिले हैं तो उन्हें अदालत के सामने मजबूती से प्रस्तुत करना चाहिए। आजम खान को भी अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का कानूनी जवाब देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

गिग वर्कर्स की सुरक्षा का सवाल

लचीले रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी

बदलती अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट आधारित सेवाओं ने काम करने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी है। आज कोई व्यक्ति मोबाइल एप्प के माध्यम से भोजन पहुँचाकर, ऑनलाइन टैक्सी चलाकर,सामान की डिलीवरी करके ,घरेलू सेवाएँ उपलब्ध कराकर या स्वतंत्र डिजिटल कार्य करके अपनी आजीविका अर्जित कर सकता है। रोजगार का यह स्वरूप गिग इकोनॉमी कहलाता है और इसमें काम करने वाले लोग गिग वर्कर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। इन श्रमिकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार काम चुन सकते हैं, लेकिन इस लचीलेपन के साथ उनकी आजीविका में असुरक्षा भी जुड़ी हुई है। नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें वेतन, भविष्य निधि, पेंशन, चिकित्सा सुविधा और सवेतन अवकाश जैसी सुविधाएँ सामान्यतः



डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा



उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिए गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा अब केवल श्रम कल्याण का विषय नहीं, बल्कि समावेशी विकास और आर्थिक न्याय की अनिवार्य शर्त बन गई है।

भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने गिग रोजगार को नई गति दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार,देश में गिग वर्कर्स की संख्या वर्ष 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। यह संख्या बताती है कि आने वाले समय में रोजगार का यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। भोजन की आपूर्ति, परिवहन,ई-कॉमर्स,घरेलू सेवाओं और विभिन्न डिजिटल मंचों पर काम करने वाले लाखों लोग शहरों की आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। एक डिलीवरी कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उसकी आमदनी तत्काल बंद हो सकती है। बीमारी के कारण कई दिन काम न कर पाने पर परिवार का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। महिलाओं के सामने मातृत्व अवकाश और आय की निरंतरता जैसी चुनौतियाँ हैं। वृद्धावस्था में नियमित पेंशन का अभाव उनकी चिंता को और बढ़ा देता है। सामाजिक सुरक्षा का मूल उद्देश्य श्रमिकों को जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों में आर्थिक सहारा देना है। गिग वर्कर्स के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है,क्योंकि उनकी आय काम की उपलब्धता, ग्राहकों की माँग,मौसम,मंचों की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं पर निर्भर करती है। कई बार मंचों द्वारा भुगतान की दरों में बदलाव या प्रोत्साहन राशि में कटौती से उनकी वास्तविक आय प्रभावित होती है। ऐसे में दुर्घटना बीमा,जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा,मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाएँ उन्हें आर्थिक संकट से बचा सकती हैं। सामाजिक सुरक्षा का लाभ केवल श्रमिक तक सीमित नहीं रहता,बल्कि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे गरीबी,असमानता और आर्थिक अस्थिरता को कम करने में भी सहायता मिलती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता,2020 में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है। इस संहिता के अंतर्गत उनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने और लागू करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रमिकों,एग्रीगेटर्स और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना तथा कल्याणकारी योजनाओं की दिशा तय करना है। 22 सदस्यीय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे बोर्ड केवल योजनाओं की अनुशंसा करने वाली संस्थाएँ न बनें,बल्कि श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनके समाधान का प्रभावी माध्यम बनें,यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन बोर्डों की भूमिका कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है।



आरक्षण की रोटी
जाति प्रमाण-पत्र बनाम अर्थ प्रमाण-पत्र

हे प्रबुद्ध प्रजा, प्रणाम! मैं आपका सेवक हूं, स्वामी हूं। मेरे हाथ में आरक्षण की रोटी है। मैं इसे लोक हित हेतु परोसना चाहता हूं; लेकिन परोसने का आधार समझ से परे है। मेरे सामने जाति है और जरूरत; जरूरत अर्थात् गरीबी। गरीबी की कोई जाति नहीं होती है,हर जाति में गरीबी होती है। गरीबों को भूख सताती है। भूख त्रासदी है। भूखे को भोजन देना मानवता है। आर्थिक समता ही समानता है। मानव निर्मित जाति का भाव हमें बांटता है। जाति अतर्क्य है,अनर्थ है, अर्थ में ही अर्थ है। जातिवाद की जड़ है-जाति प्रमाण-पत्र जो जातिगत आरक्षण का आधार है। जाति मुक्त जीवन और सम्मान सबका हक है। इसमें क्या शक है? हे प्रबुद्ध प्रजा! लोकहित हेतु किसे महत्व दूं-जातिगत आरक्षण को या अर्थगत आरक्षण को ? अब आप ही बताइए; आरक्षण की रोटी किसे परोसा जाय;मानव निर्मित जाति को या आर्थिक जरूरत को?सोचिए,विचारिए फिर बताइए....

डॉ. सुनील सावन

बंगाल की खाड़ी : प्रकृति की प्रयोगशाला से तबाही के कारखाने तक

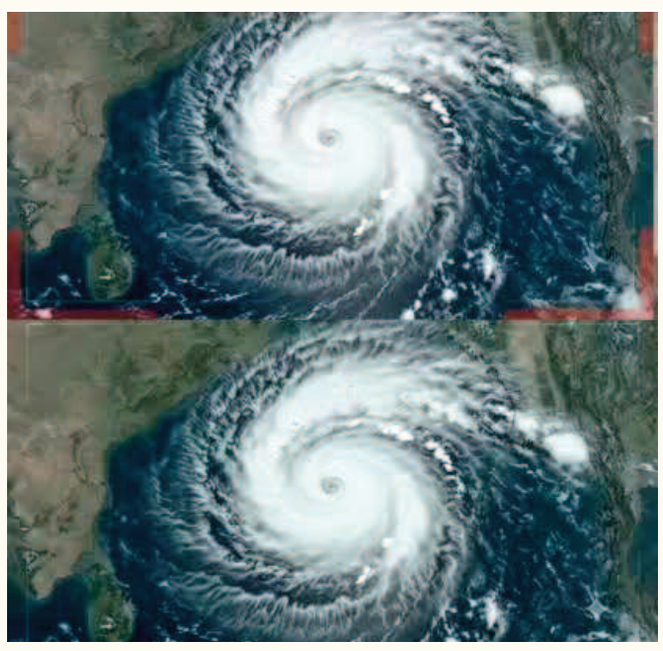
तूफान समुद्र में नहीं, हमारी लापरवाही में पल रहे हैं!
प्रकृति का पलटवार या हमारी विकास-दृष्टि की विफलता?

आसमान की रंगत बदल रही है,समुद्र का मिजाज बिगड़ रहा है और तटों पर खतरे की आहट लगातार तेज हो रही है। बंगाल की खाड़ी में एक सप्ताह के भीतर चक्रवात अर्णब और मुरासु का आना महज दो मौसमी घटनाएँ नहीं,बल्कि प्रकृति के बदलते तेवर का गंभीर संकेत है। 28 अक्टूबर को अर्णब ने आंध्र प्रदेश के तट को प्रभावित किया और 3 नवंबर की सुबह मुरासु ने फिर उसी तटीय क्षेत्र को संकट के घेरे में ला खड़ा किया। दो तूफानों के बीच इतना कम अंतराल बताता है कि बंगाल की खाड़ी अब केवल समुद्री हलचल का क्षेत्र नहीं रह गई है;वह मानो तूफानों की जन्मस्थली बनती जा रही है। समुद्र की बढ़ती तपिश और ग्लोबल वार्मिंग ने इस खतरे को और धार दी है।अब चिंता केवल अगले चक्रवात की नहीं, बल्कि उस भविष्य की है जहाँ तटीय आबादी को हर तूफान के बाद अगले तूफान का इंतजार करना पड़ सकता है।



रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

चक्रवातों की ताकत का राज अब समुद्र की गहराती तपिश में छिपा है। समुद्र का तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण तेज होता है और वातावरण में नमी व ऊर्जा का भंडार बढ़ता है। अनुकूल परिस्थितियाँ मिलते ही यही ऊर्जा चक्रवातों को अधिक प्रचंड बना सकती है। बंगाल की खाड़ी पर हुए एक शोध (साइंटिफिक रिपोर्ट्स, 2023) में 1982 से 2021 के बीच समुद्री उष्ण लहरों की 107 घटनाएँ दर्ज की गईं,जिनकी आवृत्ति में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति सामने आई। यह आँकड़ा महज वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं,समुद्र के बदलते स्वभाव की गंभीर चेतावनी है। बेशक, हर चक्रवात के लिए ग्लोबल वार्मिंग को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता,क्योंकि उसकी उत्पत्ति और तीव्रता अनेक मौसमी परिस्थितियों से तय होती हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि लगातार गर्म होती जलवायु चक्रवातों के विनाशकारी प्रभावों को और बढ़ा सकती है। मौसम अब अपने पुराने मिजाज से बगावत कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का संकट धीरे-धीरे पनपता है,लेकिन तबाही पलभर में मचा देता है। समुद्र का बढ़ता तापमान,वायु मंडलीय नमी,हवाओं की दिशा और अल नीनो जैसी परिस्थितियाँ चक्रवातों की तीव्रता व वर्षा को प्रभावित करती हैं। चक्रवातों की संख्या हर साल बढ़े, यह जरूरी नहीं,लेकिन गर्म जलवायु में शक्तिशाली तूफानों और भारी वर्षा का खतरा बढ़ सकता है। अर्णब और मुरासु ने दिखा दिया कि एक आपदा से उबरने से पहले दूसरी आ सकती है। इसलिए प्रशासन को तूफानों की गति,उनके बीच का अंतराल, संभावित वर्षा, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और तटीय आबादी की संवेदनशीलता पर एक साथ ध्यान देना होगा। चक्रवात जब तट से



टकराता है,तो सबसे पहले गरीब की थाली,किसान की फसल और मछुआरे की रोजी-रोटी उजड़ती है। जिनका जीवन समुद्र और मौसम के भरोसे चलता है,उनके लिए हर तूफान एक नई मुसीबत लेकर आता है। मछुआरे का आजीविका-सहारा समुद्र चेतावनी जारी होते ही जानलेवा खतरा बन जाता है। किसान की महीनों की मेहनत कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश में बह जाती है,तो कमजोर मकानों में रहने वाले परिवारों पर बेघर होने का भय मंडराने लगता है। पेड़ उखड़ते हैं,बिजली के खंभे गिरते हैं,सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और संचार व्यवस्था ठप्प पड़ने से राहत कार्य भी प्रभावित होते हैं। सरकारी सहायता, राशन और अस्थायी आश्रय तात्कालिक राहत तो देते हैं,लेकिन स्थायी सुरक्षा के लिए आजीविका की बहाली,सुरक्षित आवास,बीमा और आपदा के बाद शीघ्र आर्थिक सहायता भी उतनी ही जरूरी है। तरक्की की इमारतें यदि प्रकृति की नींव खोखली करके खड़ी की जाएँ,तो उनका टिकना भी मुश्किल है। बंदरगाहों,सड़कों,उद्योगों और शहरी बस्तियों का विस्तार अर्थव्यवस्था को गति देता है,लेकिन तटीय पारिस्थितिकी की अनदेखी इस विकास को विनाश में बदल सकती है। मैंग्रोव वन समुद्री लहरों और तूफानी पानी के सामने प्राकृतिक ढाल बनकर तटों की रक्षा करते हैं। इनका विनाश इस सुरक्षा-कवच को कमजोर करता है। इसलिए विकास रोकना नहीं,उसे प्रकृति के अनुकूल बनाना जरूरी है। तटीय निर्माण से पहले जोखिम का आकलन हो,प्राकृतिक जलनिकासी के रास्ते सुरक्षित रहें और संवेदनशील क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगे। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार भी तभी सार्थक होगा, जब ऊर्जा की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी साथ-साथ चले। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले समय में तटीय आबादी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। तटीय इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ेगा,वहीं खारा पानी खेतों और भूजल में घुसकर फसलों तथा पीने के पानी के स्रोतों को प्रभावित कर सकता है। तूफान थमने के बाद भी स्कूलों की बंदी,अस्पतालों पर दबाव और रोजगार का संकट लंबे समय तक बना रहता है। बच्चों और युवाओं के लिए जलवायु परिवर्तन अब किताबों का विषय नहीं, उनके भविष्य और जीवन से जुड़ी हकीकत है। ऐसे में हर तटीय जिले को पहले से तय करना होगा कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को कब और कहाँ पहुँचाना है,आश्रय की व्यवस्था कैसे होगी और बिजली-पानी जैसी जरूरी सेवाएँ कितनी जल्दी बहाल की जाएँगी। तूफान के बाद मलबा समेटना मजबूरी है,लेकिन उससे पहले तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी, स्थानीय भाषाओं में चेतावनी,समय पर निकासी,प्रशिक्षित राहत दल और चक्रवात-रोधी आश्रय जरूरी हैं। मछुआरों को समुद्र की विश्वसनीय सूचना, किसानों को मौसम के अनुकूल सलाह और तटीय समुदायों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। साथ ही,मैंग्रोव वनों की बहाली,तटीय निर्माण पर नियंत्रण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती अनिवार्य है। बंगाल की खाड़ी केवल तूफानों का रास्ता नहीं,करोड़ों लोगों की आजीविका और देश की पारिस्थितिक सुरक्षा की जीवनरेखा है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

बारकोड

रात के ठीक सवा तीन बजे जब जिला अस्पताल के नए-नवेले डायलिसिस विंग में दाखिल होइए,तो लगता है जैसे किसी फाइव-स्टार होटल के आईसीयू में आ गए हों,जहाँ बीमारी भी टाई लगाकर आती है। नीली एलईडी लाइट्स के बीच दस विदेशी मशीनें इस ऐंठ में खड़ी थीं मानो अभी-अभी जर्मनी से लोकतंत्र की नई परिभाषा सीखकर लौटी हों। गोपी अपनी माँ सावित्री को स्ट्रेचर पर धकेलते हुए हाँफ रहा था। फेफड़ों में भरता पानी जब गले से सीटी बजाता है,तो समझ लीजिए कि यमराज ने अर्जी पर पहली मुहर लगा दी है। डॉक्टर ने पर्चे पर लाल स्याही से'इमरजेंसी'घसीट दिया था और गोपी ने अपनी जेब से चमचमाता सरकारी'गोल्डन कार्ड' निकाला वही प्लास्टिक का टुकड़ा जिसे दिखाकर इस मुल्क का गरीब समझता है कि उसने सीधे विधाता के दफ्तर का पास बनवा लिया है। उसने नया,सीलबंद डायलाइजर फिल्टर मेज पर पटका। तकनीशियन ने किसी महायज्ञ के पुरोहित की तरह उस पर स्कैनर फेरा। अचानक मशीन ने एक तीखी चीख मारी और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक रहस्यमय साक्षात अभिशाप कौंधा, 'एरर कोड 404: इनवैलिड बारकोड! सत्र निरस्त।'

यहीं से शुरू होता है असली रोमांच,जिसे हमारे देश में 'प्रक्रिया' कहा जाता है। तकनीशियन ने अपनी रिवॉल्विंग कुर्सी को झूला बनाते हुए चश्मा नासाग्र पर टिकाया और उस स्वर में बोला जिसमें थानेदार मर्डर केस की तफ्तीश बंद करता है,देखो गोपी भाई,फिल्टर तो लखनऊ के सरकारी गोदाम से आया है,लेकिन इसका बारकोड मुंबई के मेन सर्वर से अभी लिंक नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर इसे घुसपैठिया मान रहा है। गोपी के पाँव काँप रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा,बाबूजी,सील पैक डिब्बा है,माँ का दम घुट रहा है...बस बाईपास करके एक बटन दबा दीजिए! तकनीशियन हँस दिया,जैसे किसी देहाती ने संसद भवन में खूँटा गाड़ने की इजाजत माँग ली हो। बोला,पागल हुए हो क्या? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,तुम्हारे गाँव की ट्यूबवेल नहीं कि तार छीलकर जोड़ दिया और पानी बह निकला। बिना डिजिटल ठप्पे के अगर हाथ भी लगाया,तो मशीन का मदरबोर्ड लकवाग्रस्त हो जाएगा और हमारे पीछे विजिलेंस का कुत्ता छूट जाएगा। मुंबई का दफ्तर सुबह दस बजे लॉगिन करेगा,तभी सर्वर हरी झंडी देगा। तब तक धैर्य रखो, सिस्टम में श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है।रोमांच जब औकात से बाहर हो जाए तो वह सीधे त्रासदी की देहरी पर सिर पटकने लगता है। बाहर सड़क पार एक प्राइवेट नर्सिंग होम का शीशमहल चमक रहा था,जहाँ गेट पर ही लिखा था कि जीवन अनमोल है, पर पहले सात हजार नकद जमा कराइए। गोपी ने काउंटर पर अपनी जेबें उड़ेल दीं तीन सौ चालीस रुपये,एक खुरदुरी बीड़ी और साइकिल की टूटी चाबी। उसने हाथ जोड़कर अपना सस्ता चीनी मोबाइल और कलाई की घड़ी तक मेज पर रख दी,पर कॉरपोरेट धर्मशास्त्र में भावनाओं की कोई रसीद नहीं कटती,वहाँ सिर्फ नोटों का स्पर्श पाकर ही ऑक्सीजन के सिलेंडर जागते हैं। वह उल्टे पाँव दौड़ा और उस सरकारी सन्नाटे में अपनी माँ के स्ट्रेचर से लिपट गया। सावित्री देवी की पथराई आँखें छत के पंखे को नहीं,सीधे अपने बेटे के लाचार चेहरे को ताक रही थीं। उनके नीले पड़ते होंठ फड़फड़ाए,गोपी...बेटा...सांस...नहीं...और फिर एक घुरघुराहट के साथ उनका हाथ गोपी की उंगलियों से फिसलकर ठंडे कंक्रीट पर बेजान झूल गया।

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

कला केंद्र से सदर रोड तक ठेले-गुमटियों की होगी शिफ्टिंग,नए वेंडिंग जोन भी बनेंगे

जाम वाले स्थानों को किया जाएगा चिह्नित,ठेला संचालकों की गणना कर जारी होंगे परिचय पत्र

-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और बाजारों में बेतरतीब ढंग से लगने वाले ठेले-गुमटियों को व्यवस्थित करने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। कला केंद्र, सर्किट हाउस,आकाशवाणी,सदर रोड, गुदरी बाजार चौक,चौपाटी और अस्पताल सहित यातायात प्रभावित क्षेत्रों में ठेले-गुमटियों को हटाकर व्यवस्थित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए शहर में नए वेंडिंग जोन चिह्नित करने के साथ ठेला संचालकों की गणना भी कराई जाएगी।

महापौर मंजूषा भगत और सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी के मार्गदर्शन में निगम आयुक्त विनय अग्रवाल के निर्देश पर मंगलवार को बाजार विभाग की सलाहकार समिति की बैठक हुई। प्रभारी बाजार विभाग अनिता रविंद्र गुप्त 'भरती' के नेतृत्व में हुई बैठक में बाजारों के व्यवस्थित संचालन और यातायात की समस्या दूर करने को लेकर कई प्रस्ताव रखे गए।

ठेला संचालकों का होगा सर्वे,जारी होंगे परिचय-पत्र

शहर के वेंडिंग और नो वेंडिंग जोन में लगने वाले स्थायी और चलित ठेले-गुमटियों की गणना कर परिचय पत्र जारी करने का प्रस्ताव रखा गया। सब्जी बाजारों में स्थायी और अस्थायी रूप से बैठने वाले व्यवसायियों का भी सर्वे कराया जाएगा। नो वेंडिंग जोन में दुकान लगाने वालों को चिह्नित कर उनके लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।



वेंडिंग जोन में मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं

बैठक में वेंडिंग जोन में नियमित सफाई,पानी,बिजली और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। पंजीकृत वेंडरों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए निगम में एकल खिड़की व्यवस्था शुरू करने तथा श्रमिक पंजीयन,स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने शिविर लगाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा चौपाटी में केवल आवंटित दुकानदारों को ही व्यवसाय की अनुमति देने, कला केंद्र की दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने,भगवानपुर में निर्माणाधीन बाजार का व्यवस्थित आवंटन और प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास पौनी-पसारी योजना की दुकानों के संचालन पर भी चर्चा की गई। निगम के उडनदस्ते को नो वेंडिंग जोन का नियमित निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया।

बैठक में पार्षद शैलेश सिंह,अशोक सोनवानी, विमला सोनी,जे. कुजूर,सालेम केरकेट्टा सहित बाजार विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। समिति ने दीपावली और छठ पूजा के बाद प्रस्तावों को पूरी तरह लागू करने का सुझाव दिया।

धनतेरस-दिवाली पर बाजार में भीड़, निगम ने बनाई अस्थायी पार्किंग व्यवस्था

धनतेरस और दिवाली पर बाजार में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने शहर में अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की है। देवीगंज रोड,सदर रोड,स्कूल रोड और जयस्तंभ चौक सहित प्रमुख बाजारों में जाम की स्थिति से बचने के लिए नागरिकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने की अपील की गई है। नगर निगम ने देवीगंज रोड पर निशांत मेडिकोज के बगल में स्थित भूमि,महामाया चौक के लिए नगर निगम स्कूल मैदान, गुदरी चौक के लिए मल्टीपर्पज स्कूल मैदान तथा ब्रह्म रोड और सदर रोड के लिए पुराने बस स्टैंड एवं राज्य परिवहन डिपो स्थित मैदान में अस्थायी पार्किंग बनाई है। निगम ने नागरिकों और बाजार आने वाले ग्राहकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की है, ताकि त्योहार के दौरान यातायात सुचारू बना रहे और आम नागरिकों व व्यापारियों को परेशानी न हो।



रजिस्ट्री के बाद भी वृद्धा को नहीं मिली जमीन की कीमत,25 लाख के सौदे में मिले सिर्फ 25 हजार

बकाया मांगने पर धमकी देने का आरोप, कलेक्टर और एसपी से लगाई न्याय की गुहार

-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद भी 73 वर्षीय वृद्धा को अपनी भूमि की पूरी कीमत नहीं मिली। ग्राम कोट निवासी जगियो दास का आरोप है कि 25 लाख रुपए में जमीन बेचने के बावजूद उन्हें अब तक केवल 25 हजार रुपए ही मिले हैं। बकाया राशि मांगने पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। शिकायत के अनुसार, जगियो दास की ग्राम कर्रा, तहसील दरिमा में 2.202 हेक्टेयर जमीन थी। आर्थिक मजबूरी के चलते उन्होंने अंबिकापुर निवासी सुरेश कुमार अग्रवाल के साथ जमीन का सौदा किया। 10 सितंबर 2025 को भूमि की रजिस्ट्री केता के नाम हो गई और बाद में नामांतरण भी हो गया। इसके बावजूद वृद्धा को पूरी रकम नहीं मिली।



मध्यस्थ पर धमकी देने का आरोप

वृद्धा ने शिकायत में सौदे के मध्यस्थ सनमोगन वानियार पर बकाया राशि मांगने पर गाली-गलौज और मारकर फेंक देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिवनाथ प्रजापति और संजय केरकेट्टा सहित अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग भी की है। वृद्धा ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर बकाया राशि दिलाने और दोषियों के खिलाफकानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

राजमिस्त्री की हथियार से हत्या,आंगन में मिला शव

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरीकला के टिकरापारा में 40 वर्षीय राजमिस्त्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह उसका शव घर के आंगन में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक अंगद चौधरी पिता घूरसाय चौधरी घर में अकेले रहता था। उसकी पत्नी कुछ माह पहले मायके चली गई थी, जबकि अन्य परिजन गांव में ही दूसरे घर में रहते हैं। परिजनों ने सोमवार रात करीब 10 बजे अंगद को घर की ओर जाते देखा था। मंगलवार सुबह उसका शव आंगन में मिला। उसके गले और सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। पुलिस को घर के भीतर टूटी कुर्सी और दीवारों व फर्श पर खून के छींटे मिले हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हमलावर और अंगद के बीच संघर्ष हुआ होगा। जान बचाने के लिए वह आंगन की ओर भागा होगा। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। हत्या किसने और क्यों की, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।



घर में घुसकर दंपती से मारपीट, बाइक चोरी का भी प्रयास

दरवाजा तोड़कर तीन युवकों ने पति-पत्नी को पीटा,शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने एक आरोपी को पहचाना

-संवाददाता-
सीतापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

थाना क्षेत्र के ग्राम डांगबुड़ा में सोमवार रात घर में घुसकर दंपती से मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अरमान एक्का अपने तीन साथियों के साथ घर में घुसा और पति-पत्नी की पिटाई कर दी। आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और धान को भी बिखेर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम डांगबुड़ा निवासी राधा लकड़ा (39) ने शिकायत दर्ज कराई है कि 1 नवंबर की रात करीब 10.30 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो रहे थे। इसी दौरान घर के बाहर खड़ी बाइक के पास आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। कुछ देर बाद अरमान एक्का और उसके दो साथी मुख्य दरवाजे को लात मारकर तोड़ते हुए घर में घुस आए। इस दौरान उनके पति अजीत राम ने चोर घुसने की आवाज लगाई तो आरोपियों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। इससे उनके दाहिने घुटने और पैर में चोट आई। पीड़िता के अनुसार,पति को बचाने पहुंचने पर तीनों आरोपियों ने उन्हें जमीन पर पटककर मारपीट की। इससे कमर के नीचे के हिस्से में दर्द हो रहा है। शोर सुनकर घर के पीछे सो रहे उनके ससुर पवन साय और सास सुखमनी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने अरमान एक्का को पहचान लिया, जबकि उसके तीन अन्य साथियों की पहचान नहीं हो सकी।

बाइक सड़क किनारे खड़ी कर भागे आरोपी

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों में से एक युवक घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले गया था, लेकिन बाद में उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया। आरोपियों ने घर में रखे धान को भी बिखेर दिया। जाते समय आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

रघुनाथपुर में सागौन और साल की लकड़ी का अवैध कारोबार,पिकअप वाहन भी बरामद

अवैध लकड़ी मिल पर वन विभाग का छापा,5 लाख से अधिक की चिरान जब्त

-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

वन विभाग की टीम ने लुंड्रा वन परिक्षेत्र के रघुनाथपुर में संचालित अवैध लकड़ी मिल पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर सागौन और साल की चिरान जब्त की है। जब्त लकड़ी की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान मौके से एक पिकअप वाहन भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार, वन विभाग को रघुनाथपुर में अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर एसडीओ अंबिकापुर कुनाल मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने सुरेश गुप्ता और आकाश गुप्ता की लकड़ी मिल पर दबिश दी। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में सागौन और साल की चिरान मिली, जिसे वन विभाग ने जब्त कर लिया।

लंबे समय से चल रहा था कारोबार

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संबंधित लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार किए जाने की बात सामने आई है।



वन विभाग ने लकड़ी और पिकअप वाहन जब्त कर लिया है।

दोनों आरोपियों के खिलाफवन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीओ कुनाल मिश्रा ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।

प्रशासनिक शिथिलता एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता पर संभागायुक्त की कार्रवाई

बिहारपुर प्रभारी तहसीलदार निलंबित

-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने एक आदेश जारी कर श्री करमचंद जाटवर,नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार, बिहारपुर,जिला सूरजपुर की कार्यशैली एवं आचरण शासकीय सेवक के विपरीत होने पर निलंबित कर दिया है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार,17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासनिक शिथिलता एवं सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरती गई है। श्री जाटवर का कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के सर्वथा विपरीत एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। श्री जाटवर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है।



आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के द्वारा श्री करमचंद जाटेवर, नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार,बिहारपुर जिला सूरजपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री जाटवार का मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला अम्बिकापुर जिला सरगुजा नियत किया गया है। उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026-27 का भव्य शुभारंभ

सात विकासखंडों के 1800 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम,लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज के मुख्य आतिथ्य में हुआ शुभारंभ,फुटबॉल को किक मारकर विधायक ने किया सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ

-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026-27 का शुभारंभ आज गांधी स्टेडियम,अम्बिकापुर में किया गया। जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग,सरगुजा के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज के मुख्य आतिथ्य में हुआ। खेल का शुभारंभ विधायक श्री मिंज ने फुटबाल को किक मारकर किया। प्रतियोगिता का आयोजन 03 से 05 नवम्बर तक किया जा रहा है। इसका शुभंकर 'गजरू' बनाया गया है। सरगुजा के खेल इतिहास में पहली बार फ्लड लाइट की रोशनी में फुटबॉल मैच का आयोजन भी विशेष आकर्षण रहेगा।

इस प्रतियोगिता में जिले के सातों विकासखंडों अम्बिकापुर,उदयपुर, बतौली, मैनपाट, लखनपुर,लुण्ड्रा एवं सीतापुर के लगभग 1800 खिलाड़ी,कोच एवं मैनेजर शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस लगभग 1000 जूनियर बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि खेले बार आघू आबो सरगुजा के मान बढ़बो के स्लोगन के साथ खिलाड़ी सरगुजा ओलंपिक में हो रहे शामिल। इस ओलंपिक प्रतियोगिता में तीरंदाजी, रस्साकसी महिला,फुटबॉल,एथलेटिक, बास्केटबाल,बॉलीबाल,कुश्ती,कराटे, कब्बडी , खो-खो एवं बैडमिंटन खेल शामिल हैं।

मुख्य अतिथि प्रबोध मिंज ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी टीम में स्थान बनाने के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन जरूरी है। खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने के लिए नियमित अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने अपने स्कूल एवं कॉलेज के दिनों के खेल अनुभव साझा करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक जिले के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है। सभी खिलाड़ी खेल भावना एवं नियमों का पालन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करें तथा संभाग,राज्य,राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना, खेल के नियमों के पालन तथा अपने जिले के गौरव एवं सम्मान को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से खेलने की शपथ दिलाई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी खिलाड़ियों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।





88 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन

सरगुजा ओलंपिक के प्रति जिले के खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में 01 अगस्त से 15 सितम्बर 2026 तक ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइन पंजीयन कराया गया, जिसमें जिले के सातों विकासखंडों से कुल 88,509 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया। इनमें 36,319 पुरुष एवं 52,190 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सर्वाधिक 48,626 खिलाड़ियों ने एथ लेटिक्स विधा के लिए पंजीयन कराया।

विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 01 से 10 अक्टूबर 2026 तक जिले के सभी सात विकासखंडों में किया गया। इसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र,मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए आवागमन एवं भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई।

खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। व्यक्तिगत खेल विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 2,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर 1,500 रुपये तथा तृतीय स्थान पर 1,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं दलगत खेल विधाओं में प्रथम स्थान के लिए 4,000 रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 3,000 रुपये तथा तृतीय स्थान के लिए 2,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं।जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 15 से 20 नवम्बर 2026 तक संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर में प्रस्तावित संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी,राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर,भरत सिंह सिसोदिया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बेहतर खेल के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रोमा श्रीवास्तव,सहायक संचालक खेल श्री रामकुमार सिंह,खेल अधिकारी,अन्य जनप्रतिनिधि, खेलप्रेमी एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे,जिला पंचायत सामान्य सभा में विकास कार्यों की समीक्षा



बलरामपुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हिरामुनी निकुंज की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत सभाकक्ष में सामान्य सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों,जनकल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श करते हुए विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धीरज सिंह देव,जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा चेरवा सहित जिला पंचायत एवं जनपद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण,जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के वर्ष 2026-27 के लक्ष्य एवं प्रगति,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों की अद्यतन स्थिति तथा खाद्य विभाग की योजनाओं एवं राशन वितरण व्यवस्था की क्रमवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष श्रीमती हिरामुनी निकुंज ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आपसी तालमेल के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी का पहला कर्तव्य है,जिसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच सशक्त समन्वय आवश्यक है। उन्होंने प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी बैठकें नियमित रूप से हों, ताकि क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में पेयजल, राशन वितरण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विषय रखते हुए उनके शीघ्र निराकरण की मांग की। सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई कर अवगत कराने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निर्वाचन साक्षरता क्लबों में 2 से 20 नवंबर तक होगी निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता,जिले के सभी स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थी ले सकेंगे भाग

बलरामपुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के स्कूलों एवं महाविद्यालयों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लबों (ईएलसी) के माध्यम से 2 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में ईएलसी वाले संस्थानों के सभी इच्छुक विद्यार्थी अपने संस्थान के क्लब के माध्यम से भाग ले सकेंगे,चाहे वे क्लब के सदस्य हों या नहीं। निबंध प्रतियोगिता 'शुद्ध मतदाता सूची का महत्व' अथवा 'मतदान का महत्व' विषय पर होगी,जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के लिए 500 से 800 तथा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए 800 से 1200 शब्दों की सीमा सुझाई गई है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मतदाता सूची तैयार करने, ईवीएम एवं वीवीपैट,मतदान तथा मतगणना प्रक्रिया पर आधारित होगी। प्रतियोगिताएं हिंदी अथवा अंग्रेजी में आयोजित की जा सकेंगी।

प्रतियोगिता संस्थान,विधानसभा क्षेत्र एवं जिला,तीन स्तरों पर होगी। 2 से 7 नवंबर तक संस्थान स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता से शीर्ष 2 विद्यार्थियों का चयन होगा,जो 10 से 13 नवंबर तक विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यहां से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के शीर्ष 10 विद्यार्थी 16 से 18 नवंबर तक जिला स्तरीय फ इनल में शामिल होंगे,जिसमें अंतिम 10 विजेताओं का चयन किया जाएगा। परिणामों की घोषणा एवं प्रमाण पत्र वितरण 20 नवंबर तक होगा। जिला विजेताओं को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मेरिट प्रमाण पत्र दिए जाएंगे,वहीं सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रविष्टियां मौलिक होनी चाहिए,नकल अथवा एआई से तैयार प्रविष्टियां तथा किसी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या विचारधारा का उल्लेख करने वाली सामग्री अमान्य होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि यह प्रतियोगिता युवाओं और भावी मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने तथा उनमें लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने जिले के सभी स्कूलों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों और ईएलसी समन्वयकों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए विद्यार्थियों से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

किसान कल्याण,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार और अधोसंरचना विकास की उपलब्धियों का किया गया प्रदर्शन

राज्योत्सव 2026 में 'सशक्त नारी,युवा उड़ान' थीम पर आधारित प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण





-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2026 में जिला जनसंपर्क कार्यालय अम्बिकापुर द्वारा आकर्षक प्रदर्शनी के माध्यम से जिलेवासियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई। 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' की थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित योजनाओं और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं, उनके उद्देश्यों,लाभों और उपलब्धियों से अवगत कराया गया। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से स्थान दिया गया। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 68 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने तथा अब तक 20 हजार 708 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 13.96 लाख महिलाओं के लखपति दीदी बनने, पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 39.73 लाख महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। कृषक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा के अंतर्गत 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित किए जाने की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राज्य के 26 लाख किसानों को मिल रहे लाभ, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 4 लाख 95 हजार 965 भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता तथा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में संग्रहण दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने और बोनस सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी भी दी गई।

पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों को रेखांकित

प्रदेश में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रयासों को रेखांकित करते हुए छत्तीसगढ़ को पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिए जाने,डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़ अभियान के माध्यम से जनजातीय, विरासत एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किए जाने की उपलब्धि प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये के प्रावधान और श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 55 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को अयोध्याधाम की निःशुल्क यात्रा कराए जाने की जानकारी भी दी गई। अधोसंरचना विकास और औद्योगिक निवेश से संबंधित उपलब्धियों में 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं,18,215 करोड़ रुपये की लागत वाली 37 सड़क परियोजनाओं तथा 4,146 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापट्टनम छह लेन एक्सप्रेस-वे को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। वहीं इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 8.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने तथा एआई मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान और 1,000 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला एआई डेटा सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी गई।

आवास योजना के तहत 24.54 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति

आवास एवं बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 24.54 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति और 20.75 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण होने की उपलब्धि प्रदर्शित की गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 41.50 लाख घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने तथा इसके लिए 4,500 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप स्थापना पर 1 लाख 12 हजार रुपये तक की सब्सिडी के प्रावधान को भी प्रदर्शनी में दर्शाया गया। युवा कल्याण, शिक्षा और तकनीकी विकास के क्षेत्र में राज्य के प्रयासों की जानकारी देते हुए 38 नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी निर्माण,मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन,इनोवेशन हब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इसके तहत 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयास आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आईआईटी/आईआईआईटी में 136, एनआईटी में 363 तथा एमबीबीएस में 82 विद्यार्थियों के चयन और 10 जिलों में 2,717 सीटों की उपलब्धता की जानकारी भी साझा की गई। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए लागू किए गए 450 से अधिक प्रशासनिक सुधारों,सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ई-ऑफिस,ऑनलाइन पेमेंट,सुगम ऐप और नियो रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही सेवा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 38 विभागों की 948 सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की पहल को भी दर्शाया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 18 जिलों के 1,544 ग्रामों के लगभग 56 हजार 569 परिवारों को लाभान्वित किए जाने की जानकारी भी प्रदर्शनी में शामिल रही।

जिला स्तरीय राज्योत्सव कार्यक्रम में 'आकांक्षा हाट' बना आकर्षण का केंद्र





छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में आयोजित जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाई गई। कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री रोमा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं एवं आजीविका गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया।इस अवसर पर नीति आयोग के आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत लखनपुर द्वारा 'आकांक्षा हाट' का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण महिलाओं एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित गोदना कला की साड़ियाँ, हस्तनिर्मित स्टॉल,चाबी के छल्ले,मिट्टी के बर्तन,बाँस की टोकरियां,सूप एवं स्थानीय खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए। आकर्षक हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने महिलाओं की कला एवं कौशल की सराहना करते हुए उत्पादों की खरीदारी भी की। 'आकांक्षा हाट' ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता,स्थानीय कला-संस्कृति के संरक्षण एवं 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने की एक सराहनीय पहल रही।

जनपद सदस्य के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान धान खरीदी केंद्र कोरजा (बिनकरा) किये जाने को लेकर कलेक्टर से किया मुलाकात



-संवाददाता-
अंबिकापुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

आज ग्राम पंचायत गुमगराकला , गुमगरा खुर्द और बगदरी के लगभग सैकड़ो किसान जनपद सदस्य नीतू धर्मेन्द्र झारिया के नेतृत्व और उस क्षेत्र के सरपंच प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनदर्शन और कलेक्टर से मुलाकात कर धान खरीदी केंद्र कोरजा किये जाने से होने वाली समस्याओ से अवगत करा जल्द ही निराकरण करने का निवेदन किया !

किसानों ने कलेक्टर से मिलकर धान खरीदी केंद्र कोरजा किये जाने से किसानो को खाद बिज़ लेने की समस्या,कोरजा से लटोरी (जमगला) समिति की दुरी पास मे ही होने के बावजूद कोरजा में ख़रीदी केंद्र बनाया जा रहा है जिस्से गुमगराकला,गुमगरा खुर्द और बगदरी के किसान नाराज है, खरीदी केंद्र का निर्धारण किसानों की सुविधा को देखकर नहीं किया गया है,क्षेत्र के किसानों की मांग है कि कोरजा खरीदी केंद्र को हटाकर गुमगरा कला या बगदर्री में होनी चाहिए !

किसानो और जनप्रतिनिधियों का साफ़कहना है यदि धान खरीदी केंद्र कोरजा के स्थान को नहीं बदला जाता है तो हमें पुराने समिति निम्हा में ही रखा जाए! इसके बाद भी अगर प्रशासन द्वारा हमारे मांगो पर अमल नहीं किया जाता है तो हम सभी किसान मिलकर चक्काजाम,धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे !!

इस दौरान जनपद सदस्य नीतू धर्मेन्द्र झारिया,पूर्व जनपद सदस्य धर्मेन्द्र कुमार झारिया,गुमगरा कला के सरपंच प्रतिनिधि शिव प्रताप सिंह उर्रे,गुमगराखुर्द के सरपंच प्रतिनिधि गुड्डू सिंह,उप.सरपंच गोलू साहू, बगदरी के सरपंच अजय उर्रे, सिंगल सिंह टेकाम,कपूर साहू,ज्ञान प्रसाद यादव,संत लाल यादव,संतोष मरावी,शिव कुमार सिंह, लालसाय,सनीलाल आदि क्षेत्र के सभी किसान उपस्थित रहे !!

जिला स्तरीय प्रतियोगिता दो श्रेणियों में होगी आयोजित

मेरिट के आधार पर दोनों श्रेणियों से 3-3 प्रतिभागियों का होगा चयन

-संवाददाता-
एमसीबी,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जनजातीय गौरव सप्ताह 2026 के अंतर्गत जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 05 नवंबर 2026 को जनजातीय गौरव ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेरिट क्रम के आधार पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव ज्ञान प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जिले से श्रेणी एक एवं श्रेणी दो में 3-3, कुल 6 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता दो श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। श्रेणी एक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ एकलव्य विद्यालय,प्रयास विद्यालय तथा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। वहीं श्रेणी दो में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। जिला स्तर पर दोनों श्रेणियों की प्रतियोगिता ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी।

आयुक्त,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,नया रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कराया जाएगा।

ग्रामीण प्रतिभाओं ने दिखाया दम,महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी

बलरामपुर में सरगुजा ओलंपिक का भव्य आगाज

-संवाददाता-
बलरामपुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ग्रामीण अंचलों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करने की दिशा में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक खेल प्रतियोगिता (2026-27) की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन जिलेभर के खेल प्रेमियों और प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बालक-बालिकाओं से लेकर महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल विधाओं में अपनी खेल भावना और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।



महिलाओं का बढ़ा उत्साह... 91 हजार से अधिक पंजीयन

इस खेल महाकुंभ को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना उत्साह है,इसका अंदाजा इसके पंजीकरण के आंकड़ों से लगाया जा सकता है।

विकासखंड स्तर पर कुल 91,995 खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कराया है, जिसमें 47,945 महिलाएं और 44,050 पुरुष शामिल हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक संख्या यह साबित करती है कि अब ग्रामीण इलाकों में खेलों के प्रति सोच तेजी से बदल रही है।







विकासखंडवार पंजीयन की स्थिति इस प्रकार रही

वाड्रफनगर: 21,932, **राजपुर:** 19,943,**रामचंद्रपुर:** 16,071, **बलरामपुर:**13,719, **कुसमी:** 10,250, **शंकरगढ़:**10,080। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर आयोजित मुकाबलों में 8,837 खिलाड़ियों (4,581 पुरुष और 4,256 महिलाएं) ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

पहले दिन इन खेलों के हुए रोमांचक मुकाबले

उद्घाटन के पहले दिन सेजेस हिंदी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान में सीनियर महिला वर्ग की रस्साकसी के साथ-साथ एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। इनमें 100 मीटर,200 मीटर, 400 मीटर दौड़,रिले दौड़,गोला फेंक,भाला फेंक,तवा फेंक,ऊंची कूद और लंबी कूद जैसी स्पर्धाएं शामिल रहीं। वहीं,पुलिस लाइन इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन और वॉलीबॉल के रोमांचक मैच खेले गए।

आगामी खेल कार्यक्रम

4 नवंबर: फुटबॉल,तीरंदाजी, खो-खो,कराटे,कुश्ती और बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं। **5 नवंबर:** कबड्डी और हॉकी के फाइनल व रोमांचक मुकाबले। यह सभी प्रतियोगिताएं सेजेस हिंदी माध्यम विद्यालय,कृषि विज्ञान केंद्र जाबर,मिशन स्कूल और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भेलवाडीह के खेल परिसरों में आयोजित की जा रही हैं। इस आयोजन से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी कला दिखाने का बड़ा अवसर मिल रहा है।



घोटालों के आरोपों से घिरा कार्यकाल...अब समिति प्रबंधक की कुर्सी पर नजर!

साधना कुशवाहा का सपना और सहकारिता विभाग की रहस्यमयी मेहरबानी

विवादों की खेती,आरोपों की फसल और अब समिति प्रबंधक की कुर्सी! सहकारिता में तरक्की का यह कैसा फार्मूला?

- आरोपों की फाइलें बंद,कुर्सी की दौड़ शुरू! साधना कुशवाहा के समिति प्रबंधक बनने की चर्चा से सहकारिता में हलचल...
- बर्खास्तगी,एफआईआर,जेल और निलंबन भी नहीं रोक पाए सपने! साधना कुशवाहा अब समिति प्रबंधक बनने की दौड़ में?
- धान शॉर्टेज के रिकॉर्ड के बीच कुर्सी का सपना! साधना कुशवाहा को आखिर किसका संरक्षण?
- कथित घोटालों की लंबी फेहरिस्त,फिर भी समिति प्रबंधक बनने की तैयारी! सहकारिता में कैसा है यह नियुक्ति तंत्र?
- पहले 2.25 करोड़ का पशु ऋण प्रकरण,फिर धान शॉर्टेज के विवाद,अब समिति प्रबंधक बनने की चाहत!
- बर्खास्तगी से बहाली और अब प्रबंधक की कुर्सी तक! साधना कुशवाहा के मामले में सहकारिता विभाग की भूमिका पर सवाल


सहकारिता में 'कुर्सी अमर है' योजना!
पहले सेवा से बाहर, फिर धान खरीदी की जिम्मेदारी, फिर भी मेहरबानी जारी!
धान का हिसाब किससे मांगे किसान? नियम पहले या 'कुर्सी' पहले?
राख खरीदी में 3559 क्विंटल कमी के बाद भी 'मेहरबानी' जारी, फिर मिली खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी और आगे फिर जिम्मेदारी मिलने की संभावना


सहकारिता में 'कुर्सी का खेल'
सेवा समाप्ति के बाद भी वापसी का रास्ता?
सोनपुर समिति में नियमों पर उठे गंभीर सवाल
सहकारिता में 'हटाओ और लौटाओ' का खेल?
सोनपुर समिति में पुराने फैसलों पर फिर सवाल


एक लाख क्विंटल धान खरीदी, खाते से 82 लाख की डेबिट! खर्च का हिसाब कौन देगा?
धान एक लाख क्विंटल,खर्च 82 लाख पार!
शिवप्रसादनगर में हिसाब की 'खिचड़ी' कौन पकाता रहा?

3559 क्विंटल से 5552 क्विंटल धान की कमी तक विवाद,अब समिति प्रबंधक बनने का ख्वाब! आखिर किसके दम पर?

घोटालों के आरोपों से घिरा कार्यकाल, फिर भी प्रबंधक की कुर्सी पर नजर! सहकारिता विभाग की मेहरबानी का रहस्य क्या?

सहकारिता में गजब का खेल! बर्खास्तगी,एफआईआर और निलंबन के बाद अब समिति प्रबंधक बनने की तैयारी?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/सोनपुर/शिवप्रसादनगर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सहकारिता विभाग में यदि जिम्मेदारी संभालने का पैमाना विवादों की संख्या,आरोपों की गंभीरता और विभागीय कार्रवाई का इतिहास है, तो फिर साधना कुशवाहा का सेवा रिकॉर्ड किसी परिचय का मोहताज नहीं होना चाहिए! पशु ऋण वितरण में 2.25 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता,धान खरीदी वर्ष 2020-21 में 3559 क्विंटल धान की कमी का आरोप, 7 जनवरी 2023 को सेवा से बर्खास्तगी, एफआईआर, जेल और वर्तमान में अग्रिम जमानत पर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, फिर धान खरीदी वर्ष 2024-25 में 67.33 हेक्टेयर के कथित फर्जी रकबा पंजीयन का विवाद और वर्ष 2025-26 में भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 5552 क्विंटल धान कम मिलने का मामला–इतने घटनाक्रमों के बाद भी यदि कोई कर्मचारी समिति प्रबंधक बनने का सपना देख रहा है,तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस सपने के पीछे कौन-सी ताकत काम कर रही है?

सपना देखना अच्छी बात है,हर कर्मचारी को आगे बढ़ने, पदोन्नति पाने और बेहतर जिम्मेदारी हासिल करने का अधिकार है,लेकिन सहकारिता विभाग कोई ऐसी प्रयोगशाला तो नहीं जहां एक के बाद एक विवादों के बीच जिम्मेदारियां बदलती रहें और हर नए पद के साथ पुराने सवालों को भी अलमारी में बंद कर दिया जाए! समिति प्रबंधक का पद कोई शोभा की कुर्सी नहीं है,जहां बैठकर केवल रुतबा बढ़ाया जाए,यह किसानों के ऋण,धान खरीदी, वित्तीय लेन-देन और समिति के प्रशासनिक कामकाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद है, ऐसे पद के लिए सेवा रिकॉर्ड,कार्यप्रणाली और जवाबदेही की कसौटी सबसे पहले होनी चाहिए,विभागीय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि साधना कुशवाहा समिति प्रबंधक बनने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए विभागीय स्तर पर दौड़-भाग भी कर रही हैं,हालांकि इस कथित प्रयास की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही समिति प्रबंधक पद पर उनकी नियुक्ति का कोई आदेश सामने आया है,लेकिन चर्चा ने सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, आखिर जिनके नाम के साथ इतने गंभीर विवाद जुड़े बताए जा रहे हैं,उन्हें समिति प्रबंधक बनाने की चर्चा किस आधार पर चल रही है? क्या विभाग ने उनके पुराने मामलों की समीक्षा कर ली है? क्या सभी आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है? क्या उन्हें संबंधित मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है? यदि ऐसा है तो विभाग को दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। और यदि मामले अभी लंबित हैं,तो नियुक्ति की पात्रता और प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।


किसानों को हमाली मिली, शिवप्रसादनगर में क्यों झड़ी?
खत्म हो चुकी तौली गई,अब रुपयों का वजन कौन करेगा?
शिवप्रसादनगर में हमाली से 1.16 करोड़ की डेबिट तक सवाल ही सवाल

2.25 करोड़ के कथित पशु ऋण घोटाले से शुरुआत,फिर जेल तक पहुंचा मामला– साधना कुशवाहा से जुड़े विवादों में सबसे गंभीर मामला वर्ष 2022-23 में सामने आए कथित 2.25 करोड़ रुपये के पशु ऋण वितरण घोटाले का बताया जाता है,आरोप है कि पशु ऋण वितरण के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं,इस प्रकरण में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, वर्तमान में वह अग्रिम जमानत पर हैं तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है, यहां सवाल यह नहीं कि न्यायालय से पहले किसी को दोषी घोषित कर दिया जाए,न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और आरोप सिद्ध होने या न होने का अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा,लेकिन विभागीय जिम्मेदारी का सवाल तो अपनी जगह खड़ा है,जिस कर्मचारी के विरुद्ध करोड़ों रुपये के कथित पशु ऋण घोटाले में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और मामला न्यायालय में विचाराधीन हो,उसके सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा किए बिना उसे समिति प्रबंधक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चा कैसे हो सकती है? क्या विभाग में नियुक्ति और जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई मानक नहीं है? या फिर मानक हैं,लेकिन उनका इस्तेमाल सुविधा के अनुसार किया जाता है? यदि सब कुछ नियमों के तहत है तो संबंधित आदेश और पात्रता का आधार सामने आना चाहिए,आखिर किसानों के पैसे और समिति के वित्तीय रिकॉर्ड की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने से पहले विभाग को अतिरिक्त सतर्कता क्यों नहीं बरतनी चाहिए?

3559 क्विंटल धान की कमी और 7 जनवरी 2023 की बर्खास्तगी—फिर वापसी का रास्ता कैसे खुला?– धान खरीदी वर्ष 2020-21 में भी साधना कुशवाहा का नाम 3559 क्विंटल धान की कमी के आरोप से जुड़ा बताया जाता है,इस मामले में लाखों रुपये की आर्थिक अनियमितता का आरोप सामने आया था,उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोनपुर समिति के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी ने कथित 2.25 करोड़ रुपये के पशु ऋण वितरण और 3559 क्विंटल धान शॉर्टेज के आरोपों के आधार पर 7 जनवरी 2023 को साधना कुशवाहा को सेवा से बर्खास्त कर दिया था,अब जरा सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर गौर कीजिए,एक ओर करोड़ों रुपये के कथित पशु ऋण घोटाले और हजारों क्विंटल धान की कमी के आरोपों के आधार पर बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है,दूसरी ओर बाद के वर्षों में वही कर्मचारी धान खरीदी केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती दिखाई देती हैं, आखिर यह जिम्मेदारी किसके आदेश से मिली? क्या बर्खास्तगी आदेश के बाद सेवा में उनकी स्थिति बदल गई थी? क्या किसी सक्षम प्राधिकारी ने बहाली या पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी किया था? यदि हां,तो वह आदेश क्या कहता है? क्या नियुक्ति से पहले पुराने मामलों की समीक्षा की गई थी? इन सवालों के जवाब सामने आए बिना विभाग की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहेंगे,आखिर बर्खास्तगी कोई सामान्य टिप्पणी नहीं होती कि आज हुई और कल भुला दी गई,उसके पीछे विभागीय प्रक्रिया,आदेश और कारण होते हैं, यदि उन कारणों में बदलाव हुआ तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए।

बर्खास्तगी के बाद वर्ष 2024-25 और 2025-26 में धान खरीदी की जिम्मेदारी किसने सौंपी?– अब सबसे दिलचस्प सवाल सामने आता है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार साधना कुशवाहा को वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 में शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाया गया। आखिर किस अधिकारी ने यह जिम्मेदारी सौंपी? किस आधार पर सौंपी? क्या उनके सेवा रिकॉर्ड और पूर्व की कार्रवाई को नजरअंदाज किया गया? क्या इस नियुक्ति के लिए कोई विशेष आदेश जारी हुआ था? यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो विभाग को नियुक्ति आदेश और उसके आधार को सार्वजनिक करना चाहिए,आखिर यह कोई निजी प्रतिष्ठान नहीं,जहां जिम्मेदारी देने का निर्णय किसी की व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ दिया जाए, यह किसानों की उपज और सरकारी धन से जुड़ी व्यवस्था है, यहां हर नियुक्ति का आधार पारदर्शी होना चाहिए।

67.33 हेक्टेयर का कथित फर्जी रकबा—शिकायत और खबर के बाद भी कार्रवाई कहां?– धान खरीदी वर्ष 2024-25 में शिवप्रसादनगर केंद्र से जुड़ा एक और गंभीर विवाद सामने आया,आरोप है कि 67.33 हेक्टेयर का फर्जी रकबा पंजीयन कर कई हजार क्विंटल धान का विक्रय किया गया,इस संबंध में शिकायत किए जाने और समाचार प्रकाशित होने की जानकारी है,लेकिन उपलब्ध विवरण के अनुसार अब तक किसी ठोस कार्रवाई का स्पष्ट ब्यौरा सामने नहीं आया है,यदि रकबा पंजीयन में गड़बड़ी हुई थी,तो राजस्व रिकॉर्ड से उसका मिलान किसने किया? संबंधित किसानों के नाम पर कितनी भूमि दर्ज थी? वास्तविक खेती और पंजीकृत रकबे में कितना अंतर था? कितने क्विंटल धान का विक्रय हुआ? क्या खरीदी केंद्र के रिकॉर्ड और राजस्व विभाग के दस्तावेजों का मिलान किया गया? शिकायत की जांच किस अधिकारी ने की और उसका निष्कर्ष क्या निकला? यह कोई मामूली कागजी गलती नहीं है,धान खरीदी व्यवस्था में रकबा पंजीयन ही किसान की पात्रता और संभावित खरीदी की मात्रा का आधार होता है,यदि 67.33 हेक्टेयर के फर्जी रकबा पंजीयन का आरोप सामने आया है,तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,लेकिन सवाल यही है कि शिकायत और खबरों के बाद कार्रवाई का परिणाम कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जांच की फाइल भी धान की बोरियों के साथ किसी कोने में रख दी गई हो?

सपना उनका,जवाबदेही विभाग की!

साधना कुशवाहा समिति प्रबंधक बनें या नहीं, इसका निर्णय नियमों और सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के तहत होना चाहिए,लेकिन उससे पहले उनके विरुद्ध सामने आए सभी आरोपों और विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है, न तो केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना उचित होगा,सहकारिता विभाग के पास अब भी अवसर है कि वह पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए,पुराने आदेश सार्वजनिक करे, शिकायतों का परिणाम बताए और समिति प्रबंधक पद की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रखे। यदि आरोप गलत हैं तो संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर मिले,लेकिन यदि अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए,आखिर सवाल एक कर्मचारी के सपने का नहीं,सहकारिता विभाग की साख का है, किसानों की मेहनत की उपज और सरकारी धन की रखवाली करने वाली व्यवस्था में क्या जवाबदेही से बड़ा कोई संरक्षण हो सकता है? अब देखना यह है कि सहकारिता विभाग इस कथित समिति प्रबंधक बनने की दौड़ को किस नजरिए से देखता है,क्या पुराने मामलों की फाइलें खोली जाएंगी,क्या नियुक्ति की पात्रता सार्वजनिक होगी और क्या कथित संरक्षण देने वालों की भूमिका भी जांची जाएगी? या फिर सहकारिता की फाइलों में एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा–आरोप पुराने, सवाल पुराने,लेकिन कुर्सी का सपना नया! किसानों को अब आश्वासन नहीं,जवाब चाहिए। सहकारिता विभाग को अब खामोशी नहीं, दस्तावेजों के साथ जवाबदेही दिखानी होगी।

वर्ष 2025-26 में भौतिक सत्यापन के दौरान 5552 क्विंटल धान कम—फिर निलंबन और बहाली का रहस्य!– विवादों की सूची में अगला मामला धान खरीदी वर्ष 2025-26 का बताया जा रहा है,इस दौरान भौतिक सत्यापन में लगभग 5552 क्विंटल धान कम पाए जाने का मामला सामने आया, इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद साधना कुशवाहा को निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई है,लेकिन इसके बाद उनकी बहाली किस आधार पर हुई,यह सवाल आज भी स्पष्ट जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है, यदि भौतिक सत्यापन में 5552 क्विंटल धान की कमी पाई गई थी,तो उस कमी की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या कमी का पूरा हिसाब लिया गया? क्या रकम जमा कराई गई? यदि जमा कराई गई तो किसने और किस आधार पर? क्या केवल राशि जमा हो जाने से विभागीय जिम्मेदारी समाप्त हो गई? क्या यह जांच की गई कि धान की कमी कैसे हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार था? और यदि साधना कुशवाहा को बहाल किया गया, तो बहाली का आदेश किसने जारी किया? उसमें क्या कारण दर्ज किए गए? क्या जांच पूरी हो गई थी? क्या उन्हें आरोपों से मुक्त किया गया था या केवल प्रशासनिक आधार पर बहाल किया गया? इन सवालों के जवाब सामने आने चाहिए, सहकारिता विभाग में कहीं ऐसा फार्मूला तो नहीं चल रहा कि पहले शॉर्टेज सामने आए,फिर रकम जमा हो और उसके बाद जिम्मेदारी का नया रास्ता खुल जाए? यदि ऐसा नहीं है, तो विभाग को पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सार्वजनिक कर इस संदेह को दूर करना चाहिए।

विवादों का रिकॉर्ड पीछे,समिति प्रबंधक की कुर्सी आगे— आखिर किसकी मेहरबानी?–विभागीय सूत्रों के अनुसार साधना कुशवाहा समिति प्रबंधक बनने के लिए प्रयास कर रही हैं। यदि यह जानकारी सही है,तो विभाग को सबसे पहले उनके पूरे सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करनी चाहिए,पशु ऋण प्रकरण, एफआईआर,न्यायालय में विचाराधीन मामला, बर्खास्तगी आदेश,धान शॉर्टेज के आरोप, 67.33 हेक्टेयर रकबा विवाद,5552 क्विंटल धान की कथित कमी,निलंबन और बहाली–इन सभी घटनाक्रमों का दस्तावेजी परीक्षण होना चाहिए,समिति प्रबंधक बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं,लेकिन सवाल यह है कि क्या समिति प्रबंधक की कुर्सी पर बैठने के लिए केवल विभागीय दौड़-भाग और कथित पहुंच पर्याप्त है? क्या किसानों के हित,वित्तीय अनुशासन और ईमानदार कार्यप्रणाली का कोई महत्व नहीं? क्या विभाग में ऐसे कर्मचारी नहीं हैं जिनका सेवा रिकॉर्ड साफ-सुथरा हो और जिन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सके? और सबसे बड़ा सवाल–यदि साधना कुशवाहा के पीछे किसी अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण है,तो वह कौन है? क्या बैंक प्रबंधन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी दावेदारी को आगे बढ़ा रहा है? क्या सहकारिता विभाग के भीतर कोई ऐसी ताकत है जो पुराने विवादों के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण पद पर देखना चाहती है? फिलहाल किसी अधिकारी की भूमिका की पुष्टि नहीं है,लेकिन विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया और निर्णय लेने वाले अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।

सहकारिता में क्या यही है तरक्की का नया पैमाना?– किसानों के लिए सहकारी समिति वह स्थान है जहां उन्हें ऋण,खाद,बीज और धान खरीदी जैसी सुविधाएं मिलती हैं, किसान अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंचता है और भरोसा करता है कि उसका धान सही तौला जाएगा,भुगतान सही होगा और समिति का हिसाब पारदर्शी रहेगा,लेकिन जब समिति की जिम्मेदारी संभालने वाले पदों को लेकर ही इतने सवाल खड़े होने लगें,तो किसानों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? यदि एक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में इतने गंभीर विवाद दर्ज बताए जा रहे हैं,तो विभाग को यह बताना चाहिए कि समिति प्रबंधक पद के लिए पात्रता की कसौटी क्या है, क्या एफआईआर,बर्खास्तगी और निलंबन का कोई महत्व नहीं? क्या न्यायालय में विचाराधीन मामले की जानकारी नियुक्ति प्रक्रिया में देखी जाती है? क्या पुराने वित्तीय विवादों की जांच पूरी होने से पहले नई जिम्मेदारी देना उचित है? कहीं सहकारिता में तरक्की का नया फार्मूला तो नहीं बन गया–पहले आरोपों में घिरो,फिर रकम का हिसाब दो,फिर बहाली का रास्ता खोजो और उसके बाद समिति प्रबंधक की कुर्सी का सपना देखो! यह व्यंग्य इसलिए है क्योंकि विभाग को इन सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ देना चाहिए, आरोपों की सच्चाई जांच से ही सामने आएगी, लेकिन जांच और जवाबदेही से बचने का रास्ता किसी के लिए नहीं होना चाहिए।

अब विभाग बताए...नियुक्ति की पात्रता क्या है और कार्रवाई का परिणाम कहां है? इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से कई सीधे सवाल हैं...

1. साधना कुशवाहा को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का प्रभारी किस आदेश से नियुक्त किया गया?
2. 7 जनवरी 2023 के बर्खास्तगी आदेश के बाद उनकी सेवा स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? बहाली या पुनर्नियुक्ति का आदेश किसने जारी किया?
3. 2.25 करोड़ रुपये के कथित पशु ऋण वितरण घोटाले में वर्तमान विभागीय स्थिति क्या है?
4. 3559 क्विंटल धान शॉर्टेज के आरोप पर विभागीय जांच का निष्कर्ष क्या है?
5. 67.33 हेक्टेयर कथित फर्जी रकबा पंजीयन की शिकायत पर क्या जांच हुई और कार्रवाई क्यों स्पष्ट नहीं है?
6. वर्ष 2025-26 में लगभग 5552 क्विंटल धान की कमी के मामले में निलंबन और बहाली का आधार क्या था?
7. क्या समिति प्रबंधक पद के लिए उनके पूरे सेवा रिकॉर्ड और लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी?
8. क्या नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के निर्णय और अनुशंसा को सार्वजनिक किया जाएगा?

CMYK



पंथी, सुआ और जसगीत से सजा राज्योत्सव

छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग में रंगा कोरिया

लोकसंस्कृति का उत्सव,विकास का संकल्प,पंथी-सुआ की थाप पर झूमा कोरिया,राज्योत्सव में गूंजा 'सशक्त नारी-युवा उड़ान'

विधायक भईया लाल राजवाड़े ने किया 26 वें राज्योत्सव का शुभारंभ,कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने महिला सशक्तीकरण और युवा प्रतिभाओं को अवसर देने पर दिया जोर...







लोकसंस्कृति का उत्सव,विकास का संकल्प,26वें राज्योत्सव में कोरिया ने बिखेरे छत्तीसगढ़ी रंग...

छत्तीसगढ़ के गौरव और विकास का उत्सव,कोरिया में धूमधाम से मना 26वां राज्योत्सव

लोककला के रंग,विकास की उमंग, राज्योत्सव में विधायक ने किया शुभारंभ, कलेक्टर ने बताई प्राथमिकताएं

संस्कृति की विरासत से विकास के संकल्प तक,राज्योत्सव में कोरिया ने दिखाई अपनी पहचान

26 साल का सफर,नई उम्मीदों का संकल्प,पंथी-सुआ की प्रस्तुतियों से सजा कोरिया का राज्योत्सव

महिलाओं को समान अवसर, युवाओं को नई उड़ान,राज्योत्सव के मंच से कलेक्टर का विकास संदेश

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने का उत्साह सोमवार को कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में पूरे उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ दिखाई दिया, रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति,परंपराओं और विकास की आकांक्षाओं का सुंदर संगम देखने को मिला,कहीं पंथी नृत्य की थाप पर कलाकारों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया तो कहीं सुआ नृत्य की पारंपरिक छटा ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जीवंत तस्वीर पेश की,जसगीत की भक्तिमय प्रस्तुति और स्कूली बच्चों के आकर्षक नृत्य ने समारोह को यादगार बना दिया,मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े ने समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिलेवासी, जनप्रतिनिधि,अधिकारी-कर्मचारी,विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत,राष्ट्रगान एवं राज्यगीत के साथ हुई,इसके बाद स्थानीय कलाकारों और स्कूली छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू किया,पारंपरिक लोकनृत्यों और गीतों के माध्यम से कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को मंच पर साकार किया,पंथी नृत्य में कलाकारों की ऊर्जा,सामूहिक तालमेल और लयबद्ध प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। वहीं सुआ नृत्य ने छत्तीसगढ़ की लोकपरंपरा और ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखाई। जसगीत की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया, बच्चों ने 'शिवा महादेवा' गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया, मिनी स्टेडियम में मौजूद लोगों की भागीदारी ने आयोजन को केवल औपचारिक समारोह न रहने देकर सांस्कृतिक उत्सव का स्वरूप दे दिया।

26 वर्षों की विकास यात्रा और अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान याद किया...

मुख्य अतिथि विधायक भईया लाल राजवाड़े ने जिलेवासियों को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया,उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पीछे लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं और जनभावनाएं जुड़ी थीं,राज्य स्थापना के बाद बीते 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है,विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ और कोरिया जिले को आगे बढ़ाने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है,विकास केवल शासन की योजनाओं और प्रशासनिक प्रयासों से पूरा नहीं होता,बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है,उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया,इस दौरान उन्होंने भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह की ओर से भी जिलेवासियों को राज्योत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर ने 'सशक्त नारी,युवा उड़ान' को बताया विकास की प्राथमिकता-कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अपने संबोधन में राज्योत्सव को गर्व,गौरव और आत्मीयता का पर्व बताया,उन्होंने कहा कि यह अवसर राज्य निर्माण के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं को याद करने के साथ बेहतर भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने का भी है, छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति,लोकगीतों,लोकनृत्यों, परंपराओं और त्योहारों से बनी है,यही सांस्कृतिक विरासत राज्य की विशिष्ट पहचान है,उन्होंने कहा कि कोरिया जिला प्राकृतिक संपदा,सांस्कृतिक विरासत और मेहनतकश लोगों की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है, जिले में पर्यटन सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं हैं,इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास और जनभागीदारी जरूरी है,कार्यक्रम की थीम 'सशक्त नारी, युवा उड़ान' पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह विषय जिले के विकास की सोच और प्राथमिकताओं को दर्शाता है,महिलाओं में ऊर्जा, जुनून और अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता है, उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है,जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार मजबूत होता है और समाज भी आगे बढ़ता है,उन्होंने युवाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षा,कौशल और अवसर मिलने से युवाओं की प्रतिभा निखरती है,यही प्रतिभा देश की प्रगति का माध्यम बन सकती है,प्रशासन का प्रयास है कि जिले की प्रत्येक महिला,युवा और बच्चा विकास की यात्रा में सहभागी बने, महिलाओं को समान अवसर और युवाओं के सपनों को उड़ान देना जिले की प्राथमिकताओं में शामिल है।

लोककलाकारों और बच्चों की प्रस्तुतियां नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ती हैं-कलेक्टर श्रीमती यादव ने स्थानीय कलाकारों और स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, छत्तीसगढ़ की लोककलाएं और पारंपरिक विधाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं,बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत का हिस्सा हैं,उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों को मंच मिलने से उनकी प्रतिभा सामने आती है और पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है, राज्योत्सव जैसे आयोजन जिले की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का भी माध्यम बनते हैं।

विभागीय प्रदर्शनी में दिखी शासन की योजनाओं और उपलब्धियों की झलक-राज्योत्सव के अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई, मुख्य अतिथि विधायक भईया लाल राजवाड़े ने कलेक्टर रोक्तिमा यादव,पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर,जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा एवं उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदर्शनी का अवलोकन किया,प्रदर्शनी में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, जिले की उपलब्धियों और विभागीय नवाचारों की जानकारी प्रस्तुत की गई,इसका उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और उनके लाभ के संबंध में जानकारी देना था,ताकि पात्र हितग्राही शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए, केवल योजनाओं का संचालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचना भी उतना ही जरूरी है,विभागीय प्रदर्शनी को नागरिकों और शासन की योजनाओं के बीच जानकारी का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए उन्होंने इसके उद्देश्य को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

सबकी सहभागिता से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा कोरिया

कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी जिलेवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं दीं,उन्होंने कहा कि कोरिया जिले का विकास सभी की सहभागिता और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है,जिले की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय संसाधन इसकी महत्वपूर्ण ताकत हैं,इनका बेहतर उपयोग कर जिले को विकास के नए अवसरों से जोड़ा जा सकता है,कलेक्टर ने जिलेवासियों से ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया,जहां महिलाओं को सम्मान और समान अवसर मिले,युवाओं के सपनों को उड़ान मिले तथा प्रत्येक नागरिक को प्रगति का अवसर प्राप्त हो। समारोह में नगर पंचायत पटना की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सिंह,गणमान्य नागरिक देवेंद्र तिवारी,कृष्ण बिहारी जायसवाल,शैलेष शिवहरे सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी,मीडिया प्रतिनिधि, विद्यार्थी,महिलाएं और बड़ी संख्या में जिलेवासी उपस्थित रहे,छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के इस आयोजन में जहां लोकगीतों और लोकनृत्यों के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान जीवंत हुई,वहीं जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के संबोधन में विकास,महिला सशक्तीकरण और युवा सहभागिता का संदेश प्रमुखता से सामने आया,पंथी,सुआ और जसगीत की प्रस्तुतियों से सजा यह समारोह कोरिया की सांस्कृतिक विरासत और बेहतर भविष्य के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना।

सूरजपुर में महिला थाना का हुआ शुभारंभ...मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया लोकार्पण

एसआई पुष्पा तिर्की बनीं जिले की पहली महिला थाना प्रभारी,महिलाओं को अब अपनी शिकायतों के लिए मिलेगी विशेष सुविधा

-संवाददाता-

सूरजपुर,03 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में सूरजपुर जिले को एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है,सोमवार, 02 नवम्बर 2026 को जिले में नवीन महिला थाना का विधिवत शुभारंभ किया गया,महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कोतवाली थाना परिसर में स्थापित महिला थाना का फीता काटकर लोकार्पण किया,इस अवसर पर एसआई पुष्पा तिर्की को जिले के प्रथम महिला थाना प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया। महिला थाना खुलने से जिले की महिलाओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराना अब आसान होगा, महिला संबंधी अपराधों एवं शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई,जांच और विवेचना सुनिश्चित करने में यह थाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवीन महिला थाने में थाना प्रभारी सहित आवश्यक पुलिस बल की पदस्थापना भी की गई है,इस अवसर पर प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी,जिला पंचायत अध्यक्ष चन्द्रमणी पैंकरा,भीमसेन अग्रवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी,रेडक्रास सोसायटी के चेयरमेन बाबुलाल अग्रवाल,जिला पंचायत उपाध्यक्ष रेखा राजलाल राजवाड़े, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नूतन विश्वास,



कलेक्टर श्रीमती रेना जमील एवं पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाला महत्वपूर्ण कदम : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े-शुभारंभ अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने महिला थाना की स्थापना को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया, उन्होंने कहा कि महिला थाना महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम में सहायक होगा, साथ ही पीड़ित महिलाओं को अपनी समस्याएं और शिकायतें सहजता से रखने का अवसर मिलेगा तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

मंत्री ने रोजनामचा में दर्ज किया शुभकामना संदेश-महिला थाना का लोकार्पण करने के पश्चात मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने थाने के रोजनामचा में शुभकामना संदेश दर्ज किया, उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि नवीन महिला थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने,महिलाओं, बच्चों एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने तथा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

महिलाओं की शिकायतों को संवेदनशीलता से सुनेगी पुलिसः पुलिस अधीक्षक-एसपी सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने कहा कि सूरजपुर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा एवं उनसे जुड़ी शिकायतों के प्रति बेहद संवेदनशील है,महिला थाना प्रारंभ होने से अब महिलाएं सीधे महिला थाने में पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी,यहां महिला थाना प्रभारी एवं महिला पुलिस स्टाफ उनकी समस्याओं को सहजता और संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे,उन्होंने कहा कि महिला थाना महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में एक प्रभावी माध्यम बनेगा,कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन सहित पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी व काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

CMYK

पीली साड़ी में शरवरी की अदाएं और आयुष्मान का इश्किया अंदाज,सावन आया है गाने ने दिलाई 90 दशक के सुनहरे दौर की याद

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोल लिया रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि फिल्म के गाने भी लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।



अब मेकर्स ने इसका नया गाना सावन आया है रिलीज कर दिया है, जो अपने म्यूजिक और रोमांटिक अंदाज से सीधे 90 के दशक की याद दिलाता है। गाने में आयुष्मान और शरवरी की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। बारिश में दोनों का रोमांस और डांस मूव्स दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं। इससे पहले फिल्म का टाइटल ट्रैक और हिमेश रेशमिया का कंपोज किया हुआ एक अन्य गाना रिलीज किया जा चुका है। अब नए ट्रैक ने फिल्म के म्यूजिकल माहौल को और खास बना दिया है।

बारिश में रोमांस करते दिखे आयुष्मान और शरवरी

सावन आया है गाने में आयुष्मान खुराना शरवरी को अपनी सुरीली आवाज से प्रभावित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं शरवरी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। गाने के कई हिस्सों में दोनों एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए नजर आते हैं। बारिश के बीच उनका डांस और रोमांटिक अंदाज गाने को एक अलग खूबसूरती देता है। इसकी धुन और फिल्मांकन में पुरानी हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गानों वाली झलक दिखाई देती है। इस गाने को श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया ने अपनी आवाज दी है। रिलीज होने के कुछ ही समय में इसे हजारों व्यूज मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी दर्शक गाने की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों को इसका म्यूजिक और बोल पुराने दौर के मेलोडियस गानों की याद दिला रहे हैं। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी हिमेश रेशमिया ने संभाली है और अब तक रिलीज हुए गानों को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है।

फैंस को पसंद आया श्रेया-हिमेश का कॉम्बिनेशन

सावन आया है रिलीज होते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया की जोड़ी की तारीफ करते हुए लिखा कि यह कॉम्बिनेशन पुराने अच्छे दिनों की याद दिलाता है। वहीं एक अन्य फैन ने गाने के बोल को शानदार बताया। किसी ने इसे सुकून देने वाला और खूबसूरत ट्रैक कहा तो कुछ दर्शकों को इसकी धुन और अंदाज काफी पसंद आया। एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि फिल्म सिर्फ अपने गानों की वजह से सुपरहिट हो सकती है, उसे कहानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि फिल्म की सफलता का फैसला रिलीज के बाद ही होगा, लेकिन गानों को मिल रही प्रतिक्रिया ने इसके प्रति दर्शकों की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।

माधुरी दीक्षित के साथ भी थिरकी थीं शरवरी

फिल्म से जुड़ा एक खास पल तब देखने को मिला था, जब शरवरी ने राजश्री प्रोडक्शंस की विरासत का जश्न मनाने के लिए दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ ये प्रेम मोल लिया के टाइटल ट्रैक पर डांस किया था। इस खास मौके पर हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री और नई पीढ़ी की अदाकारा एक साथ नजर आईं। यह पल फिल्म के प्रचार के लिहाज से भी काफी खास रहा।

27 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

ये प्रेम मोल लिया एक म्यूजिकल फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जिसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने तैयार किया है। राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। फिल्म 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गानों के जरिए दर्शकों के बीच बनी यह उत्सुकता फिल्म की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कितना असर दिखाती है।

पहली शादी टूटने के बाद फिर प्यार में रिमी टॉमी,18 साल बाद दोबारा बनेंगी दुल्हन,तलाक के 6 साल बाद चुना नया हमसफर

मलयालम सिंगर और टीवी होस्ट रिमी टॉमी जिंदगी में नई शुरुआत करने जा रही हैं। पहले पति से तलाक के बाद वह फिटनेस ट्रेनर लिबिन मैथ्यू से नवंबर में शादी करेंगी। मलयालम सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर प्लेबैक सिंगर और टीवी होस्ट रिमी टॉमी की जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक दी है। पहली शादी टूटने के करीब छह साल बाद रिमी दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। खास बात यह है कि इस खुशखबरी का खुलासा खुद सिंगर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए व्लॉग के जरिए किया है। पहले वीडियो में उन्होंने अपनी जिंदगी में नए जीवनसाथी के आने की जानकारी दी थी, वहीं अब एक दूसरे वीडियो में उन्होंने अपने होने वाले पति का नाम और उनके बारे में भी बताया है। रिमी के इस ऐलान के बाद उनके फैंस उन्हें नई शुरुआत के लिए बधाइयां दे रहे हैं।

2026 में जिंदगी में हुई नए प्यार की एंट्री

रिमी टॉमी ने अपने व्लॉग में बताया कि वह हमेशा से अकेले घूमना और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करती रही हैं। उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं एक ऐसे साथी की कमी महसूस होती थी, जिसके साथ वह अपनी जिंदगी के सुख-दुख बांट सकें। सिंगर ने बताया कि साल 2026 में उनकी जिंदगी में एक खास शख्स की एंट्री हुई और कुछ ही समय में दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। रिमी के मुताबिक, उन्हें इस रिश्ते में सबसे ज्यादा सुकून और मानसिक शांति महसूस हुई। उन्होंने इसे भगवान का दिया हुआ तोहफा बताया और कहा कि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित हैं।

कौन हैं रिमी टॉमी के होने वाले पति लिबिन मैथ्यू?



शुरुआत में रिमी ने अपने होने वाले जीवनसाथी की पहचान उजागर नहीं की थी,लेकिन 2 नवंबर को शेयर किए गए एक नए वीडियो में उन्होंने उनके नाम का खुलासा कर दिया। रिमी के होने वाले पति का नाम लिबिन मैथ्यू है,जो मुंबई में रहते हैं और बॉडीबिल्डर के साथ-साथ फिटनेस ट्रेनर भी हैं। लिबिन मूल रूप से मलयाली हैं और पिछले कुछ महीनों से रिमी के फिटनेस कोच के रूप में काम कर रहे हैं। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी नवंबर में डोंबिवली के एक चर्च में शादी करने जा रहे हैं। हालांकि,शादी की सटीक तारीख को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

पैसे और शोहरत नहीं,सुकून को दी प्राथमिकता

अपने व्लॉग में रिमी ने यह भी साफ किया कि उनके होने वाले पति न तो अभिनेता हैं,न गायक और न ही कोई मशहूर हस्ती या करोड़पति। उनके लिए जीवनसाथी चुनने का आधार पैसा और लोकप्रियता नहीं,बल्कि आपसी समझ और मानसिक शांति है। सिंगर ने कहा कि किसी रिश्ते में एक-दूसरे को समझना, खुलकर अपनी बातें साझा कर पाना और साथ मिलकर व्यक्तिगत व पेशेवर जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लिबिन के साथ उन्हें वह अपनापन और सुकून मिला, जिसकी उन्हें तलाश थी। रिमी ने अपने फैंस से इस नए सफर के लिए प्यार और आशीर्वाद देने की अपील भी की है।

11 साल बाद टूट गई थी पहली शादी

रिमी टॉमी की पहली शादी बिजनेसमैन रॉयस किझाकूडन से हुई थी। दोनों ने 27 अप्रैल 2008 को त्रिशूर में शादी की थी। हालांकि शादी के करीब 11 साल बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई। साल 2020 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए एर्नाकुलम फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। 16 अप्रैल को तलाक की प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए।

2002 में शुरू हुआ था सिंगिंग करियर

रिमी टॉमी ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक ट्रूप एंजेल वॉइस से की थी। बाद में मिमिक्री आर्टिस्ट और संगीतकार नादिरशाह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और निर्देशक लाल जोस तथा संगीतकार विद्यासागर से मिलवाया। साल 2002 में फिल्म मीसा माधवन से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म का उनका गाना चिंगमासम जबरदस्त हिट हुआ और लंबे समय तक चार्टबस्टर बना रहा। इसके बाद उन्होंने चोट्टा मुंबई,चॉकलेट,मुल्ला,बॉडीगार्ड और उदयना थारम जैसी कई फिल्मों में लोकप्रिय गाने गाए। गायिकी के अलावा रिमी ने टीवी होस्ट के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। अब वह निजी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रही हैं।

ऋचा चड्ढा ने सिंगिंग में रखा कदम, खुद लिखे अपने पहले गाने के बोल

बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा एक बार फिर अपने नए और अनोखे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। अभिनय और फिल्म निर्माण के बाद अब ऋचा ने संगीत की दुनिया में भी अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने अपनी नॉन-फिक्शन सीरीज मुसाफिरी के टाइटल ट्रैक के लिए मशहूर संगीतकार स्नेहा खानवलकर के साथ हाथ मिलाया है। खास बात यह है कि इस गाने के बोल खुद ऋचा चड्ढा ने लिखे हैं, जबकि संगीत तैयार करने और गाने को आवाज देने की जिम्मेदारी स्नेहा खानवलकर ने संभाली है। दोनों कलाकारों की यह साझेदारी फिल्मी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है।



ऋचा चड्ढा अपनी दमदार एक्टिंग और अलग तरह के किरदारों के लिए जानी जाती हैं। अब उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के जरिए दर्शकों को अपना एक और रचनात्मक रूप दिखाया है। मुसाफिरी केवल एक यात्रा आधारित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपराओं, लोगों और अनसुनी कहानियों को सामने लाने की कोशिश भी है।

मुसाफिरी के लिए ऋचा और स्नेहा की खास साझेदारी

मुसाफिरी के टाइटल ट्रैक को खास बनाने के लिए ऋचा चड्ढा ने स्नेहा खानवलकर के साथ काम किया है। स्नेहा अपने प्रयोगधर्मी संगीत और अनोखी धुनों के लिए पहचानी जाती हैं।उन्होंने इससे पहले कई फिल्मों और संगीत परियोजनाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है। खासतौर पर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का संगीत उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है।मुसाफिरी के लिए स्नेहा ने ऐसी धुन तैयार की है,जो यात्रा,जिज्ञासा और नई जगहों को जानने की भावना से जुड़ी हुई है।इस गाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि दर्शकों को भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी है।

ऋचा चड्ढा ने खुद लिखे गाने के बोल

इस प्रोजेक्ट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋचा चड्ढा ने टाइटल ट्रैक के बोल खुद लिखे हैं।स्नेहा खानवलकर ने बताया कि जब ऋचा ने उनसे सीरीज के लिए एक गाना तैयार करने को कहा,तो उन्होंने शुरुआत में एक बुनियादी धुन और लय तैयार की थी।इसके बाद ऋचा ने उसी धुन के आधार पर गाने के बोल लिखे। फिर स्नेहा ने उन शब्दों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया।इस तरह दोनों कलाकारों ने मिलकर मुसाफिरी के टाइटल ट्रैक को तैयार किया।स्नेहा ने ऋचा की रचनात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा कि वह एक स्वतंत्र विचारों वाली कलाकार हैं। उनके मुताबिक,ऋचा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई और सांस्कृतिक विषयों में रुचि का इस्तेमाल इस सीरीज को तैयार करने में किया है।



मीका सिंह का खुलासा:सहजता से बना था राय लक्ष्मी संग भीगी भीगी रातों में...

गायक मीका सिंह ने बताया कि अभिनेत्री राय लक्ष्मी के साथ उनका गाना 'भीगी भीगी रातों में'कैसे अचानक बन गया। इस सहयोग के बारे में बात करते हुए,मीका ने मीडिया को बताया कि यह विचार दोनों के बीच कॉफी पीते समय अचानक आया था, और बिना किसी पूर्व योजना के,उन्होंने अगले ही दिन इस गाने की शूटिंग कर ली। गाने के बनने के बारे में बताते हुए,मीका ने कहा,राय लक्ष्मी मेरी पुरानी दोस्त हैं,और हमारा गाना 'भीगी भीगी रातों में' बिल्कुल अचानक बन गया! इसके लिए कोई तैयारी या योजना नहीं थी। हम साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे,तभी हमने सोचा कि क्यों न साथ मिलकर कुछ किया जाए? यकीन मानिए, अगले ही दिन हमने इस गाने की शूटिंग कर ली।कभी-कभी, सबसे खूबसूरत यादें बिना किसी योजना के ही बन जाती हैं। उन्होंने आगे कहा,यह गाना मेरे सबसे पसंदीदा गानों में से एक है क्योंकि मैंने इसे अपने सबसे पसंदीदा लोगों में से एक के साथ शूट किया था। यह हमेशा मेरे लिए खास रहेगा।

खेल- समाचार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला आज

शुभमन गिल के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड,न्यूजीलैंड में 105 रन बनाते ही रचेंगे इतिहास

न्यूजीलैंड,03 नवम्बर 2026। भारतीय कप्तान शुभमन गिल साल 2026 में ओडीआई क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल करने के बेहद करीब हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 105 रन जड़ते ही वह इतिहास रच देंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से ओडीआईसीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी। शुभमन गिल के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी ओडीआई सीरीज सिर्फ कप्तानी और टीम की तैयारियों को परखने का मौका नहीं होगी, बल्कि उनके पास बल्ले से एक बड़ा इतिहास रचने का भी सुनहरा अवसर है। भारतीय कप्तान साल 2026 में ओडीआई क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने से महज 105 रन दूर हैं। अगर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में यह आंकड़ा छू लेते हैं,तो इस साल ओडीआई में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

गिल का बल्ला इस साल ओडीआई क्रिकेट में जमकर बोल रहा है। उन्होंने अब तक 11 पारियों में 895 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 111.87 और स्ट्राइक रेट 118.7 का रहा है। वह



2026 में ओडीआई क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। खास बात यह है कि उनके आसपास मौजूद दूसरे बल्लेबाज भी उनसे काफी पीछे हैं।

साल 2026 में ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

शुभमन गिल - 895
बेन डकेट - 737
पवन रत्नायके - 692
जो रूट - 680
गेरहार्ड इरास्मस - 662

गिल के पास न्यूजीलैंड की धरती पर इस उपलब्धि को हासिल करने का मौका होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की ओडीआई सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से ईडन पार्क में होगी। भारतीय टीम इस सीरीज के जरिए 2027 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी आगे बढ़ाएगी।

वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अहम सीरीज

2027 ओडीआई ओडीआई कप शुरू होने में अब करीब 11 महीने का समय बचा है। ऐसे में न्यूजीलैंड का दौरा भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीरीज में रोहित शर्मा पर भी नजरें रहेंगी। रोहित का न्यूजीलैंड की धरती पर अब तक ओडीआई शतक नहीं आया है। ऐसे में वह इस दौरे पर कुछ बड़ी पारियां खेलकर अपने रिकॉर्ड में सुधार करना चाहेंगे। वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-

न्यूजीलैंड: हेनरी निकोल्स,विल यंग, टॉम लैथम (विकेटकीपर),डेरिल मिचेल,ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान),मैट हेनरी,जैकब डफी,नाथन स्मिथ,मैथ्यू फिशर,ब्लेयर टिकनर,टिम सीफर्ट और काइल जैमीसन।

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान),विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर),नीतीश कुमार रेड्डी,अक्षर पटेल,कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज,मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह,गुरनूर बराड़,नमन धीर, आकिब नबी,ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन।

वैष्णवी शर्मा का धमाका,आईसीसी रैंकिंग में 53 स्थान की लंबी छलांग

नई दिल्ली,03 नवम्बर 2026। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा स्पिन गेंदबाज वैष्णवी शर्मा ने अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। महज 20 साल की उम्र में वैष्णवी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में ऐसी गेंदबाजी की,जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई पहचान दिलाई है। उनके शानदार प्रदर्शन का फायदा आईसीसी की ताजा महिला वनडे रैंकिंग में भी मिला है। मंगलवार,3 नवंबर 2026 को जारी रैंकिंग में वैष्णवी ने 53 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाई और गेंदबाजों की सूची में 94वें स्थान पर पहुंच गईं। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने केवल दो मुकाबलों में नौ विकेट हासिल किए थे। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय महिला क्रिकेट के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगाई हैं।



निशानेबाजी की स्टार मनु भाकर की नई पारी

अंतरराष्ट्रीय खेल राजनीति में रखेंगी कदम

नई दिल्ली,03 नवम्बर 2026। भारतीय निशानेबाजी की स्टार खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर अब खेल के मैदान से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के अधिकारों और हितों की आवाज उठाने की तैयारी में हैं। मनु भाकर अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ की एथलीट्स कमिटी के 2026 से 2030 तक के कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को उनकी उम्मीदवारी की पुष्टि की। मनु को पिस्टल वर्ग में उम्मीदवार बनाया गया है। यदि वह चुनाव जीतती हैं, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजों की समस्याओं, प्रतियोगिताओं की परिस्थितियों और खेल से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली मनु भाकर की यह नई पहल भारतीय खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली मनु खेल प्रशासन और खिलाड़ियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं।

पिस्टल वर्ग में दो सीटों के लिए मुकाबला

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने एथलीट्स कमिटी के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस चुनाव में कुल 20 सदस्य देशों के 22 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। उम्मीदवारों को राइफल, पिस्टल और शॉटगन की तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग से दो प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इस तरह छह खिलाड़ी प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से समिति में अपनी जगह बनाएंगे।मनु भाकर पिस्टल वर्ग से चुनाव लड़ रही हैं।

भारतीय रेसर जीत झाबाख का कमाल,

एशिया-पैसिफिक रैली चैंपियनशिप में रचा इतिहास

हैदराबाद,03 नवम्बर 2026। भारतीय मोटरस्पोर्ट के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हैदराबाद के प्रतिभाशाली रैली ड्राइवर जीत झाबाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2026 एफआईए एशिया-पैसिफिक रैली चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है।



अंतरराष्ट्रीय रैली प्रतियोगिता में उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय मोटरस्पोर्ट को नई पहचान दिलाई है। झाबाख ने अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय रैली सीजन में चैंपियन बनकर यह साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में बड़ी सफलता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इस जीत में उनके सह-चालक मूसा शेरिफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ की आधिकारिक अंकतालिका के अनुसार,जीत झाबाख ने कुल 73 अंक हासिल करके चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 35 अंक आगे रहे। पूरे सीजन में उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा और उन्होंने सभी राउंड में अंक अर्जित किए। खास बात यह रही कि किसी भी रैली में उन्हें रिटायर नहीं होना पड़ा। जीत झाबाख की सफलता भारतीय रैली रेसिंग के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले प्रयास में ही खिताब जीत लिया। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कठिन रास्तों, अलग-अलग मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। हर राउंड में निरंतरता बनाए रखना उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा।इस ऐतिहासिक जीत में मूसा शेरिफ ने सह-चालक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका प्रतीक कुमार जायसवाल आ0/पति मोहन लाल जायसवाल जाति निवासी बौरीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर,जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-बौरीपारा,शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1800/7 रकबा 180 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/ आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-16.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-02.11.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./ब-121/2026-27

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि आवेदक सुनील कुमार,सुजीत कुमार,अनिल कुमार,अंकित कुमार एवं सुरेश्वरी आ. स्व. कौशल किशोर सिंह निवासी शीतला वार्ड,बाबूपारा,अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर -09 मोहल्ला शीतला वार्ड,नगर अम्बिकापुर स्थित प्लाट नम्बर 3447/4 रकबा 0.21 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भू-तल पर रकबा 154 वर्गमीटर पर आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित ब्लूप्रिंट नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर,जिला- सरगुजा छ0ग0 में प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है ।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-12.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः-28.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(तीन)

मैं अजीत एक्का (माता / पिता / पालक का नाम) सुपुत्र पत्नी राम एक्का निवासी उदारी, सरगुजा, छ0ग0 एतद द्वारा सूचित किया जाता मै ग्राम पटारा पारा उदारी सरगुजा, छ0ग0 का स्थाई निवासी हूं यह कि मै अपने नाबालिक पुत्री सिया एक्का (SIYA EKA) से बदलकर एलिन रोस एक्का ALIN ROS EKKA करवाना चाहता हूं। मै पुत्री का नाम बदलकर यदि कोई गैर कानूनी काम करता/करती हूं तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

मै पत्नी/पती गीता एक्का (पत्नी/पती का नाम) को हमारे नाबालिग पुत्र/पुत्री के नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं है।जिसके लिए हस्ताक्षर कर रहा रही हूं तथा अपने पूरे होशोहवास में रहकर सपथ पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

सपथकर्ता
अजीत एक्का

CMYK

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में किया विकसित भारत संकल्प पार्क का लोकार्पण

एसआईआर पर चर्चा के लिए स्पेशल सेशन बुलाएंगे,राहुल गांधी ने नकली संसद में चर्चा का नाटक किया,संसद का मजाक बनाया : शाह

रायपुर,03 नवंबर 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-16 में विकसित भारत संकल्प पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने पार्क परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को चिरस्थायी बनाने और भावी पीढ़ियों तक राष्ट्र निर्माण का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प पार्क का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर को हरित,स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरकार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर बहस में शामिल होने की चुनौती भी दी। अमित शाह ने कांग्रेस पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माओवादियों की असंवैधानिक'जनताना सरकार'का समर्थन किया है। साथ ही,हाल ही में एक नकली संसद का आयोजन कर संसद का मजाक उड़ाया है। शाह नवा रायपुर में राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली प्रदेश की विभूतियों को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया।



संसद में दो-दो हाथ करने की चुनौती'

अमित शाह ने कहा...राहुल गांधी में हिम्मत है तो आइए, हाथ में संविधान लेकर घूमने से संविधान का समर्थन नहीं होता। आचरण संवैधानिक होना चाहिए। आपने पार्लियामेंट को रोककर रखा है, पेन में लेकर रखा है। संसद चलने दीजिए,दो-दो हाथ करने दीजिए,देश की जनता को मालूम चल जाएगा कि सच कौन है और झूठ कौन है। अमित शाह ने कहा...कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी नक्सलवाद का समर्थन करते हैं। गैर-संवैधानिक सरकारों का समर्थन करते थे। अभी-अभी उन्होंने नकली संसद बनाकर संसद का भी मखौल उड़ाया। वहां चर्चा का नाटक किया। राहुल जी, मोदी सरकार हर इश्यू पर चर्चा के लिए तैयार है। हम स्पेशल सेशन बुलाकर एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं।



कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन किया

अमित शाह ने कहा... कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन किया। 2010 में पी. चिदंबरम ने कहा था कि नक्सलियों को हथियार डालने की जरूरत नहीं है, आपस में सिर्फ बातचीत कीजिए,गोली मत चलाइए। चिदंबरम साहब,इस तरह से हिंसा नहीं रुकती। जिसको भी सरेंडर करना है,वह हथियार डालकर सरेंडर करे। उन्हें हम मेनस्ट्रीम में लाएंगे,नहीं तो हमारे जवान दो-दो हाथ करेंगे।

आदिवासियों के मानवाधिकार पर बोले शाह

अमित शाह ने कहा...नक्सलवाद का समर्थन करने वाले और मानवाधिकारों के नाम पर आवाज उठाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मानवाधिकार हाथ में बंदूक लेकर विकास रोकने के लिए होता है? क्या गरीब आदिवासियों का मानवाधिकार नहीं होता है?

'नक्सलवाद ने छीना बच्चों का बचपन'

अमित शाह ने कहा...जिस धरती पर सांस्कृतिक गलियारा होना था, वहां रेड कॉरिडोर बनाया गया था। जिस जंगल में महुआ, तेंदूपत्ता और लोकगीत निकलने चाहिए थे,वहां बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए थी,उसे स्कूल से अगवा कर बंदूकें थमा दी गईं। स्कूल को उड़ा दिया गया। जिस सड़क से विकास का रास्ता बनना था, उसे उड़ा दिया गया। अमित शाह ने कहा...रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल तक विकास के काम हुए, लेकिन उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। नक्सलवाद को खत्म करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। उसी वक्त आदिवासी क्षेत्र के विकास की कल्पना की गई थी, लेकिन वह अधूरी रह गई। आपने फिर से छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को हटाकर भाजपा सरकार को मौका दिया। इसके 2 महीने में हमने नक्सल उन्मूलन का संकल्प लिया।

शाह बोले...रायपुर बनेगा पीपल सिटी

शाह ने कहा...वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में रायपुर में 5 लाख पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। पीपल सिटी बनने के बाद हमारा रायपुर दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण मित्र शहर बनने जा रहा है। इसके लिए अलग-अलग जगहों पर आयोजन हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को दुनिया में पहचान दिलाई

अमित शाह ने कहा...छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए पंडुम और बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। करमा,राउत नाचा,पंडवानी जैसी कई लोककलाओं के साथ ढोकरा कला,बेलमेटल,काष्ठ शिल्प और कोसा कला को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर दशहरा की 75 दिन चलने वाली अनोखी परंपरा को विष्णुदेव सरकार ने एक नई पहचान दी है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक के जरिए लाखों युवा अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यहां की वेशभूषा,खानपान और लोकगीतों को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के संस्कार-समानता,सेवा और सच्चाई

अमित शाह ने कहा...यह इतने सालों से लिए गए संकल्पों की सिद्धि है। नक्सलमुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया था। मोदी जी और विष्णुदेव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के समर्पण और विकास में बड़ा योगदान देने वाले कई महानुभावों को यहां सम्मानित किया गया। गुरु घासीदास का संदेश और गुरु नानक जी की सेवा का संदेश समानता,सेवा और सच्चाई का है। यही छत्तीसगढ़ के संस्कार हैं। अमित शाह ने कहा...अटल जी ही थे,जिन्होंने 2000 में राज्य की स्थापना की।

सीबीआई टीम सौरभ चंद्राकर को लेकर रायपुर पहुंची

6 हजार करोड़ के सट्टा ऐप का मुख्य आरोपी,आज होगी स्पेशल कोर्ट में पेशी

रायपुर,03 नवंबर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम लेकर रायपुर पहुंची। उसे फ्लाइट ई6 2307 से दिल्ली से रायपुर लाया गया। उसे एयरपोर्ट के गेट नंबर-2 से ले जाने की तैयारी थी,लेकिन मीडियाकर्मियों की मौजूदगी के कारण उसे गेट नंबर-1से बाहर निकाला गया। इसके बाद अधिकारी उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए। इस दौरान कुछ देर के लिए एयरपोर्ट की लाइट भी बंद हो गई थी। सौरभ पर करीब 6 हजार करोड़ रुपए के सट्टा घोटाले में शामिल होने का आरोप है। सीबीआई उसे ओमान से प्रत्यर्पण के बाद भारत लेकर आई है। सोमवार को उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उसे सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि आरोपी को 4 नवंबर 2026 या उससे पहले रायपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाए। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले से जुड़ी 13 स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को सौंपी थीं। इनमें से 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा श्रेष्ठ भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।



देवउठनी एकादशी पर स्थानीय अवकाश घोषित...20 नवंबर को रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के सरकारी दफ्तरों में रहेगी छुट्टी

रायपुर,03 नवंबर 2026। राज्य सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख बदल दी है। अब 20 नवंबर (शुक्रवार) को देवउठनी एकादशी पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 9 नवंबर (सोमवार) को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया था। बाद में गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को बदलकर 20 नवंबर को किया गया है। यह स्थानीय अवकाश नवा रायपुर अटल नगर और रायपुर शहर में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं के लिए लागू होगा। हालांकि,बैंक, कोषालय और उप कोषालय में इस दिन छुट्टी नहीं रहेगी।



छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि..कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की ई-केवाईसी में सभी राज्यों में प्रथम

रायपुर,03 नवंबर 2026। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वीबी-जीरामजी के अंतर्गत श्रमिकों की ई-केवाईसी में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रदेश ने अकुशल श्रमिकों की ई-केवाईसी में 91.37 प्रतिशत उपलब्धि के साथ देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संयुक्त रैंकिंग में चौथा तथा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार छत्तीसगढ़ ने कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की ई-केवाईसी में 82.28 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज कर सभी राज्यों में पहला तथा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संयुक्त रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दोनों श्रेणियों में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था और श्रमिकों के डिजिटल सत्यापन की दिशा में प्रदेश की महत्वपूर्ण सफलता है। केंद्र सरकार की 03 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वीबी-जी राम जी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 79 लाख 23 हजार 503 पंजीकृत अकुशल श्रमिकों में से 76 लाख 20 हजार 979 श्रमिकों का आधार सीडिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 72 लाख 39 हजार 364 श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इस प्रकार प्रदेश ने 91.37 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय स्तर पर इस श्रेणी में लद्दाख 97.59 प्रतिशत, मिजोरम 97.42 प्रतिशत और त्रिपुरा 92.79 प्रतिशत के साथ क्रमशः पहले तीन स्थानों पर हैं, जबकि छत्तीसगढ़ 91.37 प्रतिशत उपलब्धि के साथ चौथे स्थान पर है।



मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में खनन एवं कोयला क्षेत्र की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न

खनिज संपदा का समुचित उपयोग कर छत्तीसगढ़ को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाएंगे : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर,03 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रदेश के खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर खनिज संसाधनों का समुचित, वैज्ञानिक और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि खनिज संपदा का लाभ केवल औद्योगिक विकास तक सीमित न रहे,बल्कि इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों,विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों तक पहुंचे।

खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, निवेश,रोजगार सृजन और समावेशी विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय आज अपने निवास कार्यालय रायपुर में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी.किशन रेड्डी की उपस्थिति में आयोजित खनन एवं कोयला क्षेत्र की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रदेश में खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, कोयला उत्पादन,क्रिटिकल एवं रणनीतिक खनिजों के विकास,जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि के उपयोग तथा खनन गतिविधियों में आधुनिक तकनीक के समावेश सहित विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम है। देश की बढ़ती औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप खनिज संसाधनों का अन्वेषण और उपयोग किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आवश्यकताओं,रोजगार के अवसरों और प्रभावित समुदायों के हितों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा,जब खनिज संपदा से प्राप्त आर्थिक लाभ प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खनिज प्रशासन में पारदर्शिता, तकनीक के अधिकतम उपयोग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। खनिज ऑनलाइन 2.0,डिजिटल निगरानी व्यवस्था और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से खनन गतिविधियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर के जनजातीय समुदायों को टिन अयस्क का बेहतर मूल्य दिलाने और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए टीन पोर्टल जैसी पहल प्रारंभ की गई है।



छत्तीसगढ़ सरकार के नवाचारों और खनन क्षेत्र में तकनीकी सुधारों की केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने की सराहना

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों,राजस्व वृद्धि और तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और वे देश में जहां भी जाते हैं,राज्य सरकार के अच्छे कार्यों और प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। विशेष रूप से खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल,ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग,खनन गतिविधियों की स्टार रेटिंग और डिजिटल निगरानी व्यवस्था की उन्होंने प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने खनिज राजस्व बढ़ाने और खनन क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहनीय बताया। उन्होंने बस्तर के जनजातीय समुदायों से टिन अयस्क की पारदर्शी खरीदी और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विकसित TIN पोर्टल की भी विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाने और तकनीक के माध्यम से व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

आयुष्मान में गड़बड़ी...छत्तीसगढ़ के 16 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द

एजेंट्स के जरिए बुलाते थे मरीज,रायपुर के 8 हॉस्पिटल शामिल,बिलासपुर-दुर्ग में भी एक्शन

रायपुर,03 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों के इलाज के नाम पर गड़बड़ी को लेकर पिछले दिनों छापेमारी की गई थी। अब गड़बड़ी करने वाले 16 निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने इन अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।19 अस्पतालों की जांच में 16 में अलग-अलग तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। इनमें मरीजों से इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे लेना, बिना जरूरत भर्ती करना,इलाज के पैकेज में गलत कोड डालकर ज्यादा राशि लेना और फर्जी दस्तावेज तैयार करना शामिल है। सबसे ज्यादा 8 अस्पताल रायपुर के हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक,16 अस्पतालों में सबसे ज्यादा 11 में मरीजों से अतिरिक्त पैसे वसूलने की शिकायत सही पाई गई।

7 अस्पतालों में बिना जरूरत मरीजों को भर्ती किया गया था। 5 अस्पतालों में इलाज के पैकेज की गलत कोडिंग मिली। इसके अलावा 6 अस्पतालों में एजेंटों के जरिए मरीज लाने और 2 अस्पतालों में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले सामने आए हैं।



इन 16 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द : स्वास्थ्य विभाग की जांच में जिन अस्पतालों में गड़बड़ी मिली,उनमें रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर समेत दूसरे जिलों के अस्पताल शामिल हैं।

3 अस्पतालों में बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली : जांच के दौरान तीन अस्पतालों में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई। इनमें बिलासपुर का मेहता चिल्ड्रन नर्सिंग होम,रायपुर का विजन सेंटर आई हॉस्पिटल और सरगुजा का डीएचटी अस्पताल शामिल है।

नर्सिंग होम एक्ट के तहत अलग से होगी जांच : स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त संचालक इंद्रजीत बर्मन के मुताबिक,जांच में गड़बड़ी मिलने वाले अस्पतालों पर आयुष्मान योजना के तहत कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अलग टीम बनाई गई है। फिलहाल 16 अस्पतालों पर हुई कार्रवाई आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन तक सीमित है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई अलग प्रक्रिया है।

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन...कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जुटे मंत्री सांसद-विधायक,कार्ययोजना को लेकर चर्चा जारी

रायपुर,03 नवंबर 2026। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी रायपुर के बोरियाकला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चुनाव कार्ययोजना को लेकर बैठक चल रही है। इसमें प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री,सांसद और विधायक शामिल हुए हैं। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने और संगठन की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा,प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी भारती,प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन,अखिलेश सोनी और डॉ. नवीन मार्कंडेय मौजूद हैं। इनके अलावा सांसद-भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडेय,क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी सहित प्रदेश सरकार के मंत्री,सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। इसमें निकाय क्षेत्रों में संगठन की सक्रियता बढ़ाने,चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करने और स्थानीय स्तर पर पार्टी की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रदेश संगठन के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के बीच चुनावी कार्ययोजना को लेकर समन्वय बनाने पर भी जोर है।



तूफान मुरासु का असर...रायपुर में तेज बारिश,कोहरा छाया,छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बदला मौसम

रायपुर,03 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान'मुरासु' का असर दिखने लगा है। मंगलवार शाम रायपुर में तेज बारिश हुई। शहर में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। शाम को धुंध देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों और 4 नवंबर को 15 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट है।'अर्नब' तूफान के चार दिन बाद 'मुरासु'आंध्र प्रदेश के ओंगोल के पास तट से टकराया। इस दौरान 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी दिख रहा है।

रायपुर में बादल छाए रहेंगे,बारिश के आसार : मौसम विषेशज्ञों के मुताबिक, राजधानी रायपुर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।



जगदलपुर में सबसे ज्यादा बारिश : पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में एक-दो जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश जगदलपुर में रिकॉर्ड की गई। यहां 22 मिमी बारिश दर्ज हुई। रायपुर में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में दर्ज किया गया।

रायपुर में बादल छाए,हल्की बूंदाबांदी हुई : चक्रवात मुरासु के असर से राजधानी रायपुर में तेज बारिश हुई। दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और शाम के समय घना कोहरा भी देखने को मिला। हालांकि,प्रदेश में बारिश का असर सीमित रहा।

मौसम विभाग के मुताबिक, एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जगदलपुर में सबसे ज्यादा 22 मिमी बारिश हुई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)